

“सटीकता ऊर्जा को तथा समय गति को नियंत्रित करती है”

- कोनर में मेकग्रेनर द्वारा

एक अभूतपूर्व संकटकाल की पृष्ठभूमि में, वर्ष 2020-21 राजकोषीय मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। आर्थिक गतिविधि में रुकावट के कारण राजस्व संग्रह में कमी, कमजोर लोगों, छोटे व्यवसायों, और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पर महामारी के नतीजों को कम करने के लिए अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं ने उपलब्ध सीमित राजकोषीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बनाया। संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के ग्रॉस मार्केट बरोविंग के लक्ष्य को 7.8 लाख करोड़ रुपये के बजट आकलन से संशोधित कर 12 लाख करोड़ कर दिया गया।

इसलिए, भारत ने कई देशों द्वारा अपनाए गए फ्रंट-लोडेड बड़े प्रोत्साहन पैकेज के विपरीत अर्थव्यवस्था की उभरती स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त एक अंशांकित दृष्टिकोण अपनाया। भारत की राजकोषीय नीति ने इस समझ को प्रतिबिंबित किया कि कुल/ऐग्रिगेट मांग, विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए, बचत करने के लिए एहतियाती उद्देश्यों को दर्शाती है, जो समग्र अनिश्चितता अधिक होने पर अनिवार्य रूप से ज्यादा होता है। इसलिए, महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान जब अनिश्चितता अधिक थी और लॉकडाउन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, भारत ने विवेकाधीन खपत/उपभोग को बढ़ाने की कोशिश में कीमती वित्तीय संसाधनों को बर्बाद नहीं किया। इसके बदले, नीति ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण/ट्रान्सफर, छोटे व्यवसायों के लिए आपातकालीन ऋण और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम शामिल था। अनलॉक चरण के दौरान, जब अनिश्चितता में गिरावट आई और एक तरफ उप-बचत करने के लिए एहतियाती मकसद था, और दूसरी ओर आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, भारत ने समग्र माँग पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजकोषीय खर्च में वृद्धि की। इस प्रकार, भारत की मांग-नीति, इस विचार को रेखांकित करती है कि ऐक्सेलरैटर पर दबाव डालते समय ब्रेक को दबाना केवल अपशिष्ट ईंधन बर्बाद करना है।

पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था की वसूली के कारण, मासिक राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है। मासिक जीएसटी संग्रह ने पिछले 3 महीनों के लिए लगातार 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो दिसंबर 2020 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कर प्रशासन/टैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन में सुधारों ने गति में पारदर्शिता, जवाबदेही की प्रक्रिया निर्धारित की है और इससे भी महत्वपूर्ण बात की, कर प्राधिकरण के साथ एक ईमानदार करदाता के अनुभव को बढ़ाता है, इस प्रकार कर अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। 2020-21 के लिए व्यय नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय घटक पर जोर देने के साथ व्यय के पुनः प्राथमिकताकरण पर केंद्रित थी। राजस्व में कमी और वर्ष के दौरान उच्च व्यय की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार को 2020-21 में वित्तीय चूक दर्ज करने की उम्मीद है। हालांकि राजकोषीय समेकन के मार्ग से यह विचलन क्षणिक हो सकता है क्योंकि राजकोषीय संकेतक अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ प्रतिक्षेप करते हैं। इस प्रकार, मध्यावधि में एक स्थायी राजकोषीय मार्ग को सक्षम करने के लिए जीडीपी की वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना निर्णायक होगा

परिचय

2.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2020 में एक अभूतपूर्व संकट का अनुभव किया। कोविड-19 महामारी ने देशों को लॉकडाउन का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जिसका आर्थिक गतिविधि, वित्तीय बाजारों और समाज के कमजोर वर्गों के अस्तित्व पर अचानक और तीव्र प्रभाव पड़ा। सदमे और अनिश्चितता के इस चरण के बीच बड़े पैमाने पर राजकोषीय उपायों, वैश्विक जीडीपी के 12 प्रतिशत की राशि, महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर उठाए गए थे। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति उपायों के संयोजन में, संकट के समय में एक प्रभावी नीति उपकरण के रूप में उभरी।

2.2 महामारी के लिए भारत सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अन्य देशों से अलग थी। कई अन्य देशों के विपरीत, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के पुनः प्रवर्तन के लिए एक फ्रंट-लोडेड भव्य प्रोत्साहन पैकेज चुना, भारत सरकार ने एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण अपनाया। शुरुआत में दृष्टिकोण था की लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण में समाज के गरीब और कमजोर लोगों और विशेष रूप से व्यापार क्षेत्र (विशेषकर एमएसएमई) के लिए एक कुशन प्रदान करना था। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम, जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर, साथ ही साथ क्रेडिट के लिए सरकार की गारंटी, वित्तीय समय सीमा का स्थगन आदि शामिल थे। अर्थव्यवस्था की क्रमिक अन-लॉकिंग के साथ, राजकोषीय प्रोत्साहन का ध्यान घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों से बढ़ाया गया है जैसे कि पूंजीगत व्यय, उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन और खपत बढ़ाने की मांग को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

2.3. यह अध्याय महामारी के प्रकोप से पहले और बाद में भारत में राजकोषीय विकास की समीक्षा करता है। यह चालू वित्त वर्ष में महामारी के लिए राजकोषीय प्रदर्शन और नीतिगत प्रतिक्रिया की चर्चा के साथ शुरू होता है, इसके बाद 2020-21 में कर प्रशासन में पेश किए गए प्रमुख सुधारों पर खंड है। अध्याय/चैप्टर तब केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार के वित्त में मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का एक विस्तृत विश्लेषण देता है, और 2020-21 के लिए दृष्टिकोण के स्नैपशॉट के साथ समाप्त होता है।

कोविड-19 महामारी के लिए राजकोषीय स्थिति और प्रतिक्रिया

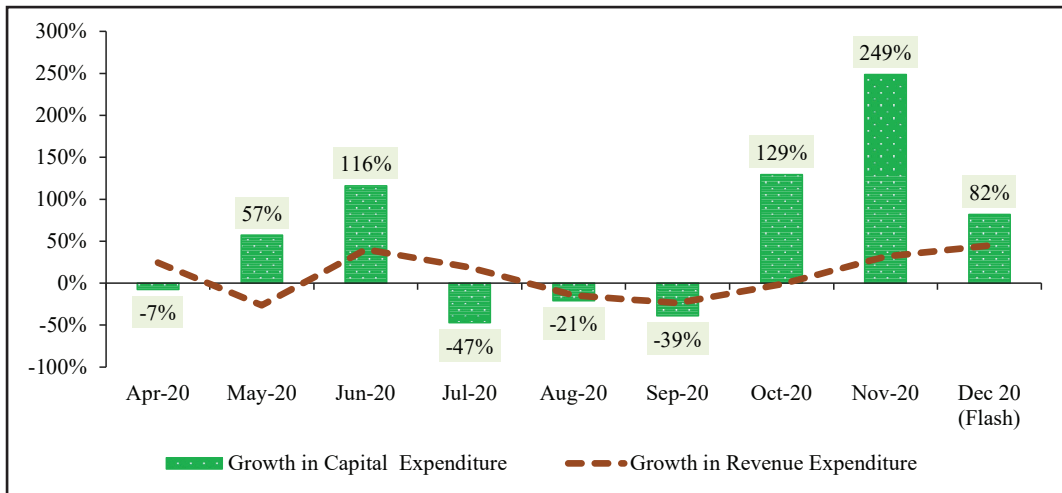
2.4 वर्ष 2020-21 की महामारी ने अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय चुनौतियों को आवश्यक बना दिया है, जो अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं की विशेषता थी, जो कमजोर लोगों के लिए जीविका और आजीविका के बुनियादी साधन सुनिश्चित करने, एमएसएमई क्षेत्र के लिए राहत के उपाय, अतिरिक्त स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं से निपटने के लिए कोविड-19 से लड़ने और मांग को बढ़ावा देने के उपायों के लिए निर्देशित थे। इस अवधि के दौरान, सरकार ने व्यय के प्रबंधन में सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड रणनीति का पालन किया।

2.5 वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान, मंत्रालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। श्रेणी शर्ष में मंत्रिमंडल/मंत्रालय जनता को राहत या कल्याण प्रदान कर रहे थे। इन मंत्रालयों/मंत्रिमंडलों पर कोई व्यय प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और वास्तव में बढ़ा हुआ आवंटन उन्हें उपलब्ध कराया गया था। अन्य मंत्रालय/मंत्रिमंडल जो सीधे तौर पर महामारी में शामिल नहीं थे, उन्हें 'बी' श्रेणी में रखा गया और प्रति तिमाही उनके बजट का 20% खर्च करने की अनुमति दी गई। महामारी की स्थिति में कम प्राथमिकता वाले मंत्रालयों/मंत्रिमंडलों को 'सी' श्रेणी में रखा गया था और पहली दो तिमाहियों में अपने बजट का 15% खर्च करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, श्रेणी बी और सी मंत्रालयों/मंत्रिमंडलों में भी, घरेलू पूंजीगत व्यय पर खर्च की अनुमति इन उच्चतम सीमा से परे की थी। इस वर्गीकरण ने सरकार को यह सुनिश्चित करने में सक्षम किया कि राजस्व प्राप्तियों में तीव्र संकुचन के बावजूद आवश्यक गतिविधियों के लिए धनराशि पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई थी, और पुनः प्राथमिकता के लिए दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण किया गया था।

2.6 तीसरी तिमाही के प्रभाव से, व्यय की उच्चतम सीमा को संशोधित पूर्ण वर्ष के आवंटन के आधार को ढीला/रिलैक्स कर दिया गया था। संशोधित आवंटन से अर्थव्यवस्था पर सबसे सकारात्मक प्रभाव या तो फिर से विकास या तो कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में उन क्षेत्रों में व्यय का एक बड़ा पुनः प्राथमिकताकरण हुआ। संशोधित आवंटन के भीतर मंत्रालयों को व्यय का समय तय करने की अनुमति दी गई थी। पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के बावजूद, पहले दो तिमाहियों में पूंजीगत व्यय की गति को प्रतिबंध क्षेत्रों/कंटेनमेंट जोन में गतिविधि प्रतिबंधों के कारण रोका गया था, और ठेकेदारों और श्रमिकों की अक्षमता या अक्षमता के कारण कार्यों को पूरा करने के लिए।

2.7 तीसरी तिमाही में गति और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, सरकारी व्यय की गति में तेजी आई है। महामारी से राहत के लिए दूसरा, सरकार ने उत्पादक घरेलू पूंजीगत व्यय पर अधिकतम प्राथमिकता दी है जिसका अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है। अप्रैल से दिसंबर 2020(फ्लैश)2 तक का पूंजीगत व्यय 3.17 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय से 24% अधिक था। कुल व्यय में भी 11% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 21.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल से दिसंबर 2020(फ्लैश) के दौरान 23.4 लाख करोड़ रुपये हो गई। मासिक व्यय के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2020 के अंतिम तीन महीनों के दौरान पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में अक्टूबर में कुल 9.5 प्रतिशत, नवंबर में 48.3 प्रतिशत और दिसंबर(फ्लैश) में 50.2 प्रतिशत की कुल व्यय में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2020 के आखिरी तीन महीनों के दौरान पूंजीगत व्यय अक्टूबर में 129.5 प्रतिशत, नवंबर में 248.5 प्रतिशत और दिसंबर(फ्लैश) में 81.9 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में था (चित्र 1)। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि समय-समय पर व्यय के संकट, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय, स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिबंधों में रुकावट के बाद, राजकोषीय मृग के लिए विकास “bang” को अधिकतमीकृत किया गया है।

चित्र 1: 2019-20 के अनुरूप महीनों में वित्त वर्ष 2020-21 की मासिक व्यय में वृद्धि

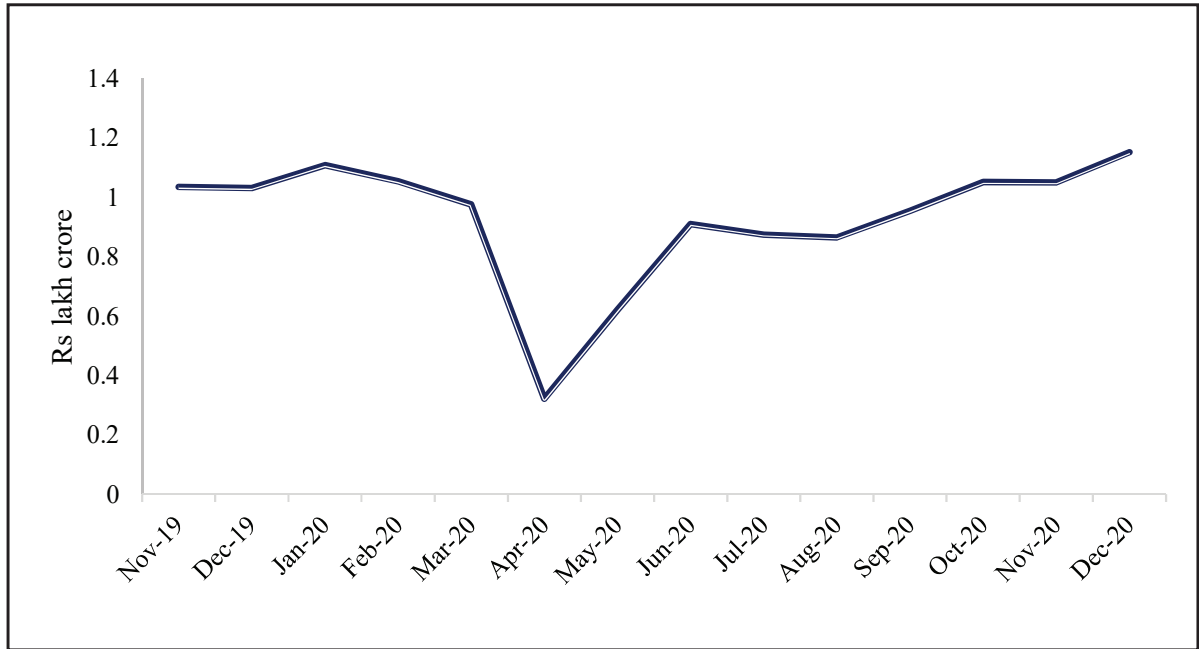


स्रोत: व्यय विभाग

2.8 राजस्व मोर्चे पर भी वसूली स्पष्ट है, क्योंकि मासिक सकल जीएसटी संग्रह ने पिछले 3 महीनों (चित्र 2) से लगातार 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है। दिसंबर 2019 (चित्र 3) से अधिक जीएसटी राजस्व में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद, दिसंबर 2020 के महीने के लिए मासिक जीएसटी राजस्व 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा। जीएसटी लागू होने के बाद से यह सबसे अधिक मासिक जीएसटी संग्रह है। जीएसटी संग्रह में रिकवरी तेजी से आर्थिक सुधार पोस्ट महामारी और जीएसटी चोरों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी

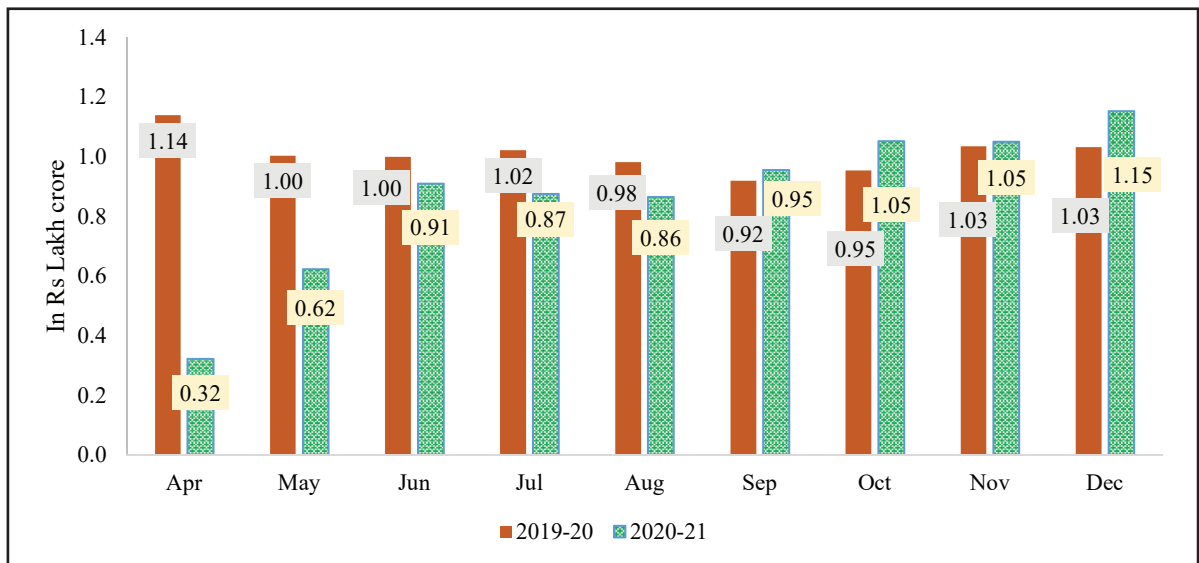
अभियान और हाल ही में शुरू किए गए कई व्यवस्थागत बदलावों के साथ नकली बिल के कारण हुई है, जिसके कारण अनुपालन में सुधार हुआ है।

चित्र 2: 2020-21 के दौरान जीएसटी संग्रह में वसूली



स्रोत: राजस्व विभाग

चित्र 3: 2020-21 के दौरान जीएसटी संग्रह में प्रवृत्ति



स्रोत: राजस्व विभाग

2.9 शेष खंड अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि के लिए राजकोषीय संकेतकों और उनके घटकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2020-21 के लिए सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2020 के अंत में केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा 114.8 प्रतिशत 2019-2020 में इसी अवधि के दौरान की तुलना में बीई का 135.1 प्रतिशत रहा (तालिका 1). महामारी से उत्पन्न स्थितियों

की भयावहता को देखते हुए, भारत सहित अधिकांश देशों में आर्थिक दृष्टि से तनाव हो रहा है, घाटा आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। सरकार द्वारा आवश्यक संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के सकल बाजार उधार का लक्ष्य बजट अनुमान 7.8 लाख करोड़ रुपये से 12 लाख करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया था।

तालिका 1: 2020-21 के लिए अनंतिम परिणाम (नवंबर 2020 तक)

	2020-21 बीई	लाख करोड़ रुपये में		संबंधित बीई का प्रतिशत		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)		
		2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)	2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)	2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)	
1	राजस्व प्राप्तियां	20.21	9.83	8.13	50.1	40.2	13.0	-17.3
2	सकल कर राजस्व	24.23	11.74	10.26	47.7	42.4	0.8	-12.6
3	राज्यों को सौंपा गया	7.84	4.22	3.34	52.1	42.6	-2.3	-20.7
4	कर राजस्व (नेट केंद्र के लिए)	16.36	7.51	6.88	45.5	42.1	2.6	-8.3
5	गैर कर राजस्व	3.85	2.33	1.24	74.3	32.3	67.8	-46.6
6	गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	2.25	0.29	0.18	24.2	8.1	10.4	-37.5
7	गैर ऋण प्राप्तियां	22.46	10.12	8.31	48.6	37.0	12.9	-17.9
8	कुल व्यय	30.42	18.20	19.06	65.3	62.7	12.8	4.7
9	राजस्व व्यय	26.30	16.06	16.65	65.6	63.3	13.0	3.7
10	पूंजीगत व्यय	4.12	2.14	2.41	63.2	58.5	11.7	12.8
11	राजस्व घाटा	6.09	6.23	8.52	128.4	139.9	13.0	36.8
12	राजकोषीय घाटा	7.96	8.08	10.76	114.8	135.1	12.7	33.1
13	प्राथमिक घाटा	0.88	4.66	6.92	1076.5	785.3	26.5	48.5

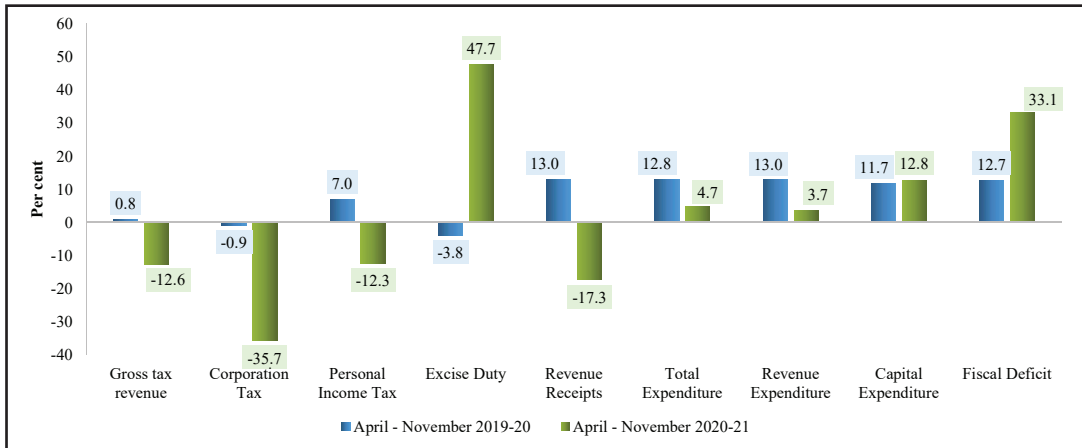
स्रोत: सीजीए मासिक लेखा; बीई: बजट एस्टीमेट/अनुमान

चित्र 4: 2020-21 में राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि दर (नवंबर 2020 तक)

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

2.10 महामारी के प्रकोप के बाद गैर-ऋण प्राप्तियां आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि (चित्र 4) के सापेक्ष -17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस कमी को गैर-ऋण प्राप्तियों के सभी घटकों यानि की शुद्ध कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नवंबर 2020 तक गैर-कर राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष 46.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यह अप्रैल से नवंबर 2019 तक लाभांश/डिविडेन्ड और मुनाफे में 0.88 लाख करोड़ रुपये की कमी के कारण हुआ, जो बीई का 45.4 प्रतिशत था।

चित्र 4:(नवम्बर 2020) तक में राजकोषीय संकेतकों को वृद्धि दर



स्रोत: सीजीए मासिक लेखें

2.11 2020-21 के पहले आठ महीनों के दौरान सकल कर राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.26 लाख करोड़ रुपये, बीई का 42%, 12.6 प्रतिशत कम था। यह गिरावट उत्पाद शुल्क को छोड़कर सभी प्रत्यक्ष करों और प्रमुख अप्रत्यक्ष करों में नकारात्मक वृद्धि के कारण थी। विशेष रूप से, प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी ने सकल कर राजस्व में 92 प्रतिशत की कमी का योगदान दिया। पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष 1.48 लाख करोड़ रुपये के जीटीआर में हुई कमी में से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी को निगम करों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, व्यक्तिगत आय करों के कारण 0.3 लाख करोड़ रुपये की कमी हुई और अप्रत्यक्ष करों के कारण रुपये 0.14 लाख करोड़। नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स बीई के 27.3 प्रतिशत और बीई के 36.8 प्रतिशत थे।

2.12 अप्रैल से नवम्बर 2020 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में गिरावट केंद्र के लिए सीमा शुल्क और जी एस टी वसूली में कमी के कारण थी। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान केंद्र के लिए सीमाशुल्क राजस्व बना आकलन का 45.71% और जी एस टी की वसूली बजट आकलन का 48% हुई थी। यह कमी उत्पाद शुल्क के माध्यम से राजस्व संग्रह से आंशिक रूप से ऑफसेट थी, जो पिछले साल की समान अवधि के सापेक्ष राजकोष के पहले आठ महीनों के दौरान 48 प्रतिशत बढ़ी। कम वैश्विक तेल की कीमतों का लाभ उठाने और म्यूटेड राजस्व संग्रह के लिए कुछ कुशन बनाने के लिए 2020-21 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था। कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए किए गए उपायों की एक श्रृंखला अनुबंध में प्रस्तुत की गई है। अनुपालन और वैधानिक कार्यों के लिए समय सीमा के विस्तार द्वारा सेवाओं और व्यक्तियों का समर्थन करने पर केंद्रित ये उपाय, उद्योग / व्यापार के साथ कार्यशील पूंजी / नकदी की उपलब्धता में सुधार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग या व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित करना ताकि कर दाता और विभाग के बीच भौतिक इंटरफेस को कम किया जा सके, दवाओं / दवाओं की शीघ्र निकासी हो सके /कोविड-19 उपचार / रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षा और चिकित्सा उपकरण।

2.13 कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल बाजार स्थितियों ने विनिवेश प्राप्तियों के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जो गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का एक प्रमुख घटक है। बजट 2020-21 में चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश आय से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें वित्तीय संस्थानों में विनिवेश के लिए 90,000 करोड़ रुपये की परिकल्पना की गई थी। 20 जनवरी, 2021 को, सरकार 15,220 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही, जिसमें से 443 करोड़ रुपये इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) (मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)) के माध्यम

से जुटाए गए और 10,169 रुपये की पेशकश ऑफर फॉर सेल (रुपये 4924 करोड़ - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) (एचएएल), रुपये 771 करोड़ - भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और रुपये 4474 करोड़ - भारतीय रेलवे सफाई और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से की गई थी, रुपये 2770 बायबैक (करोड़ 156 करोड़ रुपए - केआईओसी, रुपए 1065 करोड़-एनटीपीसीलिमिटेड, रुपए 173 करोड़ -आरआईटीईएस लिमिटेड) और रुपये 1376 करोड़ - एनएमडीसी लि.), और अन्य लेनदेन से रु 1838 करोड़ लिए गए हैं। वर्ष के दौरान, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जो वाणिज्यिक उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की मांग करता है। सरकार सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में खोलने की आवश्यकता को स्वीकार करती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परिभाषित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का ध्यान सीपीएसईयों के एक महत्वपूर्ण निजीकरण अभ्यास पर जोर देना है और एयर इंडिया, बीपीसीएल, सीओएनसीओआर और एससीआई जैसे बड़े सीपीएसईयों के बड़े-टिकट रणनीतिक बिक्री / निजीकरण को गति देना है।

2.14 वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय नीति ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित व्यय मांगों को पूरा करने के लिए व्यय के पुनर्गठन और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया है। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान कुल सरकारी व्यय बजट अनुमान के 62.7 प्रतिशत पर रुका था, जबकि अप्रैल से नवंबर 2019 में यह 65.3 प्रतिशत था। 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में 2020-21 के पहले आठ महीनों के दौरान राजस्व व्यय में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्योंकि नवंबर 2020 तक के लेखा आकड़े यह दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के प्रथम आठ महीनों के दौरान सब्सिडी में 14% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 2 देखें) चालू वर्ष के दौरान संशोधित आकालनों में सब्सिडी व्यय पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वैश्विक पेट्रोलियम कीमतों में गिरावट ने 2020-21 के दौरान एक महत्वपूर्ण राजकोषीय शॉक अक्टूबर के रूप में काम किया, क्योंकि इससे पेट्रोलियम सब्सिडी में गिरावट आई और उत्पाद शुल्क से राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई (पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण)।

तालिका 2: प्रमुख सब्सिडीयों पर व्यय

आइटम	बजट अनुमान (रुपए लाख करोड़ में)		अप्रैल से नवंबर (रुपए लाख करोड़ में)		पिछले वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि की दर (अप्रैल -नवम्बर)		
	2020-21	2018	2019	2020	2018	2019	2020
कुल प्रमुख सब्सिडी	2.28	2.19	2.35	2.02	6.3	7.3	-14.0
खाद्य सब्सिडी	1.16	1.42	1.32	1.16	5.3	-7.2	-12.0
पोषक तत्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी	0.24	0.20	0.22	0.16	14.9	11.3	-29.6
यूरिया सब्सिडी	0.48	0.33	0.51	0.50	4.6	52.7	-1.8
पेट्रोलियम	0.41	0.23	0.30	0.20	8.1	27.7	-31.9

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

2.15 लॉग टर्म एसेट और अवसंरचना के निर्माण का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 25,000 करोड़ रुपये से सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजी उपकरण पर पूंजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान को बढ़ाया था। यह बजट 2020-21 में अनुमानित रूप से 4.12 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त है। अप्रैल से नवंबर 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय 2019-20 में इसी अवधि में 12.8 प्रतिशत बढ़ा है।

2.16 पिछले महीनों के दौरान, राजस्व संग्रह में वसूली के सकारात्मक संकेत मासिक जीएसटी संग्रह में सकारात्मक वृद्धि और अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020 के महीने के लिए राजस्व प्राप्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 2019 के संबंधित महीनों के सापेक्ष देखे गए हैं। हालाँकि, आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, विशेष रूप से व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आय में गिरावट, वस्तुओं और सेवाओं की खपत और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई है, यह उम्मीद की जाती है कि 2020-21 के दौरान कर राजस्व बजट अनुमान से कम हो सकता है। इसलिए महामारी और प्रत्याशित राजस्व की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष के दौरान घोषित प्रोत्साहन पैकेजों से संबंधित व्यय की समवर्ती मांग को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बजट अनुमान को पार कर सकता है। कोविड-19 के प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय नीति प्रोत्साहन पैकेज का विवरण बॉक्स 2 में देखा जा सकता है।

2.17 कोविड-19 से प्रेरित राजकोषीय प्रणाली पर इस आघात को ध्यान में रखते हुये, इसलिए महत्वपूर्ण चिंता यह है कि क्या मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति की रणनीति को विकास या राजकोषीय नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। सर्वेक्षण के खंड 1 में अध्याय 2 इस पर विस्तार से चर्चा करता है। संकटों के समय में विरुद्ध आवर्ती विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निजी उपभोग व्यय और निजी निवेश पर गुणक प्रभावों के माध्यम से जीडीपी में वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इस तरह उच्च जीडीपी वृद्धि से मध्यम अवधि में आय के संग्रह में आसानी होगी, और इससे एक स्थायी राजकोषीय मार्ग संभव होगा।

बॉक्स 1: दुनिया भर में कोविड-19 के लिए राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया

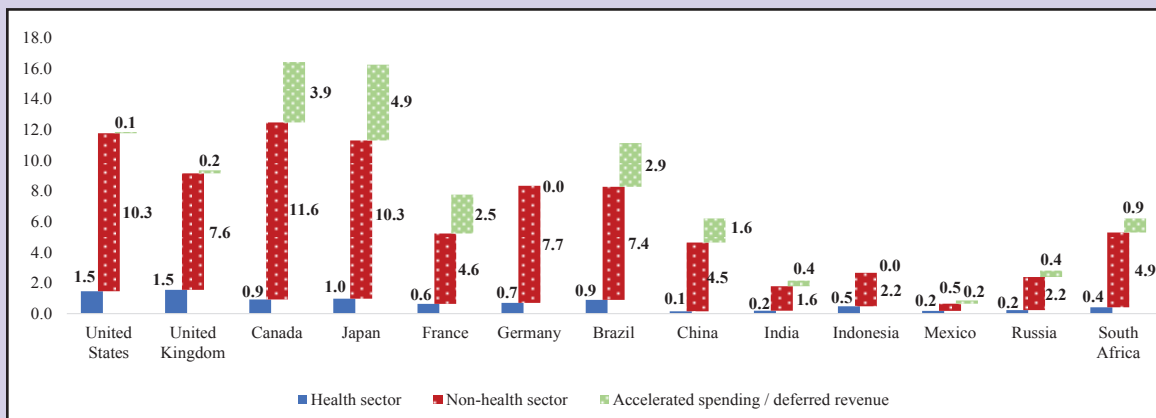
मांग को बढ़ावा देने और लॉकडाउन चरण के बाद अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव के खिलाफ जीवन और आजीविका की रक्षा के उद्देश्य से राजकोषीय नीति के उपायों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। अपनाए गए राजकोषीय उपायों में विविधता थी, जिसमें सीमा उपायों के ऊपर, सीमा उपायों के नीचे और आकस्मिक देयताएँ (गारंटी, अर्ध-राजकोषीय संचालन) शामिल थी।

‘लाइन-से-ऊपर’ उपायों में वे शामिल हैं जिनके लिए राजकोषीय घाटे, सरकारी ऋण, और अल्पावधि में बढ़ती हुई जरूरतों की पूरी लागत परिलक्षित होती है। इन उपायों में अतिरिक्त खर्च (उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं और बेरोजगारी लाभ) शामिल हैं; पूंजी वृत्ति और लक्षित स्थानान्तरण (उदाहरण के लिए, मजदूरी सब्सिडी या प्रत्यक्ष स्थानान्तरण); या कर उपाय (उदाहरण के लिए, कर कटौती या अन्य राहत) मानक बजट चैनलों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। ‘लाइन-से नीचे’ उपायों को आम तौर पर परिसंपत्तियों के निर्माण में शामिल माना जाता है, जैसे कि इक्विटी इंजेक्शन, ऋण, संपत्ति की खरीद आदि, जिसका राजकोषीय घाटे पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन वे ऋण को बढ़ा सकते हैं या नकदी (आईएमएफ राजकोषीय मॉनिटर अप्रैल 2020) को कम कर सकते हैं।

सितंबर, 2020 तक कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न लाइन-से-ऊपर उपायों और अन्य नकदी/लिक्विडिटी समर्थन उपायों की संरचना, चित्र 5 और तालिका 3 में देखी जा सकती है। आईएमएफ के इन अनुमानों से पता चलता है कि भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत के बराबर लाइन उपायों की घोषणा की और अन्य तरलता सितंबर, 2020 तक जीडीपी के लगभग 5.3 प्रतिशत के उपायों का समर्थन किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जीडीपी के 1.7 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राजकोषीय उपायों को भारत सरकार ने अक्टूबर और नवंबर 2020 में पेश किया था (देखें बॉक्स 2)। हालाँकि भारत के उपाय अन्य

विकसित देशों की तुलना में छोटे थे, लेकिन वे अर्थव्यवस्था में सुधार की सुविधा के लिए पर्याप्त थे। यह भारत को भविष्य में राजकोषीय संसाधनों को तैनात करने के लिए अधिक बड़ा एल्बो रूम छोड़ देता है।

चित्र 5: रेखा/लाइन उपायों से ऊपर (जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में) -सितंबर तक



स्रोत: आईएमएफ फिस्कल आउटलुक, अक्टूबर 2020।

11 सितंबर, 2020 तक कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की प्रतिक्रिया द्वारा घोषित प्रमुख वित्तीय उपाय शामिल हैं

तालिका 3: नकदी /लिक्विडिटी सहायता उपाय (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) -सितंबर तक

	लाइन/रेखा उपायों के नीचे: नकदी /इक्विटी इंजेक्शन, ऋण, परिसंपत्ति खरीद या ऋण धारणाएं।	आकस्मिक देयताएँ-गारंटी	आकस्मिक देयताएँ-क्वासी-राजकोषीय संचालन
संयुक्त राज्य अमेरिका	0.3	2.2	
यूनाइटेड किंगडम	0.0	16.5	
कनाडा	0.2	4.0	
जापान		3.0	20.7
फ्रांस	0.9	14.8	
जर्मनी	6.0	24.8	
ब्राजिल	1.0		5.3
चीन		0.4	0.9
भारत	0.3	4.5	0.5
इंडोनेशिया	0.2	0.9	
मेक्सिका	0.2		0.3
रूस	0.1	0.5	0.5
दक्षिण अफ्रीका		4.1	0.1

स्रोत: आईएमएफ राजकोषीय आउटलुक अक्टूबर 2020

बॉक्स 2: भारत के सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन

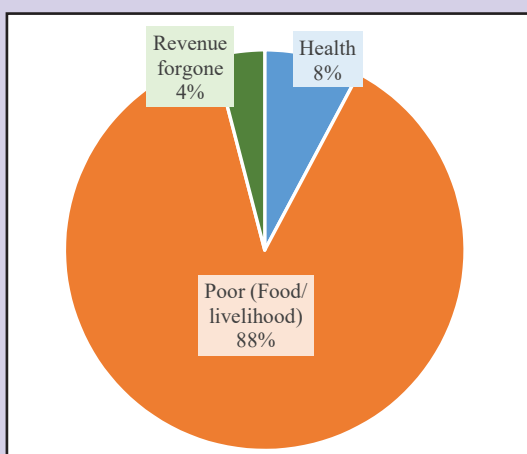
कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की एक लचीली वसूली की सुविधा और लॉकडाउन के चलते, भारत सरकार और आरबीआई ने कुल मिलाकर 29.87 लाख करोड़ रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि की घोषणा की, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 15% है। इसमें से 9% सकल घरेलू उत्पाद का प्रोत्साहन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रोत्साहन को निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रदान किया गया था:

- c. विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज, 13-17 मई 2020 से घोषित किया गया।
- b. 12 अक्टूबर 2020 को घोषित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के उपाय।
- c. 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत उपायों की घोषणा की गई।

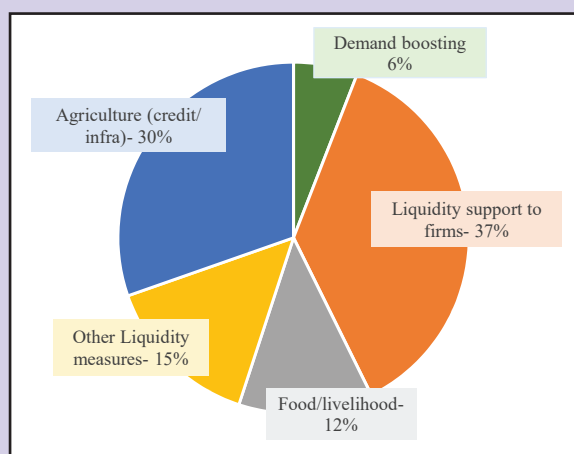
इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि कुछ अन्य देशों द्वारा अपनाए गए राजकोषीय नीति दृष्टिकोण के विपरीत, जिसमें एक ही बार में बड़ी मांग प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन चरणबद्ध तरीके से पेश किया गया था। मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों और छोटे व्यवसायों के लिए एक तकिया प्रदान करने के उपायों पर केंद्रित लॉकडाउन के शुरुआती चरण में विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई। इसमें गरीबों और कमजोर, आजीविका कार्यक्रमों, गारंटियों और नकदी /लिक्विडिटी बढ़ाने वाले उपायों के लिए सीधे खाद्य हस्तांतरण शामिल थे। इसके बाद, लॉकडाउन और प्रतिबंधों को स्थिर खोलने के साथ, उपभोग की मांग को फिर से बढ़ाने के लिए मांगने वाले पक्ष को प्रोत्साहन दिया गया था। जब लॉकडाउन के हटने के बाद आर्थिक सुधार शुरू हुआ, तो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन/इन्सेन्टिव जैसे निवेश बढ़ाने के उपायों, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के कदमों पर प्रोत्साहन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रोत्साहन के उपायों के मिश्रण में यह परिवर्तन, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है, यह दर्शाता है कि राजकोषीय नीति में एक लचीली वसूली को सक्षम करने के लिए एक उभरती हुई स्थिति के लिए अनुकूलन करने का लचीलापन था।

चित्र 6: कोविड-19 की प्रतिक्रिया में घोषित प्रोत्साहन उपायों का मिश्रण

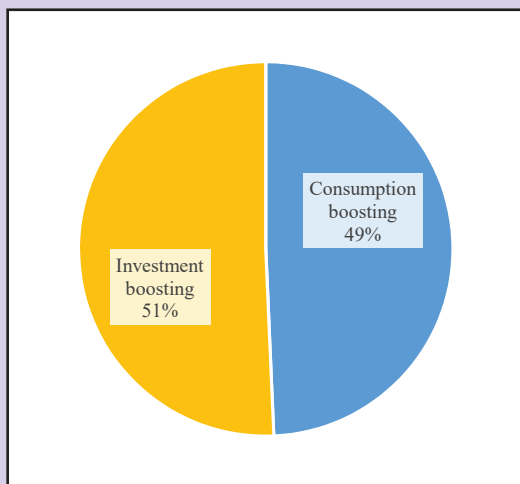
मार्च 2020 (1,92,800 करोड़ रुपये)



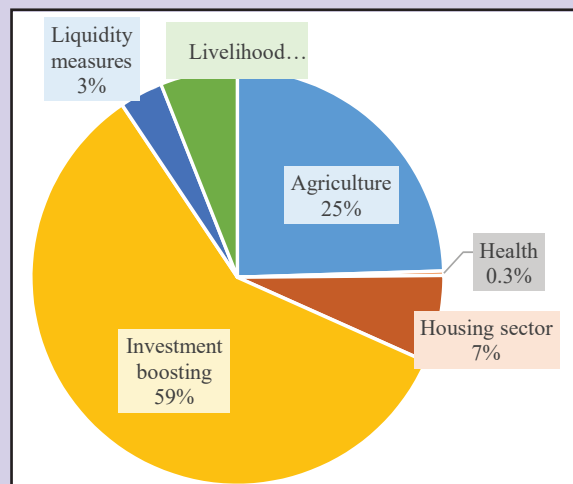
मई - जून 2020 (11,85,561 करोड़ रुपये)



अक्टूबर 2020 (73,000 करोड़ रुपये)



नवंबर 2020 (2,65,080 करोड़ रुपये)



सरकार द्वारा दी गई राजकोषीय प्रोत्साहन की अनुक्रमणिका नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है:

तालिका 4: राजकोषीय प्रोत्साहन- आत्मनिर्भर भारत पैकेज

उपायों की अनुक्रमणिका	राशि (करोड़ रुपए)	जीडीपी' के % के रूप में
मार्च 2020		
कुल प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा	1716441	8.8
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज	170000	0.87
स्वास्थ्य उपायों के बारे में प्रधान मंत्री की घोषणा	15000	0.08
22.03.2020 से घोषित कर उपायों के कारण हुई राजस्व की हानि	7800	0.04
मई 2020		
प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	20000	0.10
अतिरिक्त एमजीएनआरईजीएस आवंटन	40000	0.21
व्यापार और श्रमिकों के लिए ईपीएफ समर्थन	2800	0.01
ईपीएफ दरों में कमी	6750	0.03
डीआईएससीओएम के लिए नकदी इंजेक्शन	90000	0.46
टीडीएस / टीसीएस दरों में कमी	50000	0.26
2 महीने के लिए प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति	3500	0.02
एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन डबल्यू /सी सुविधा	300000	1.54
तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण	20000	0.10
एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से इक्विटी इन्फ्यूजन	50000	0.26
एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए विशेष नकदी योजना	30000	0.15
एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0	45000	0.23
मुद्रा शिशु ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता	1500	0.01
स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष क्रेडिट सुविधा	5000	0.03
हाउसिंग सीएलएसएस-एमआईजी	70000	0.36
नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी	30000	0.15
केसीसी के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट	200000	1.03

खाद्य माइक्रो उद्यम	10000	0.05
उपर से कुल: ऑपरेशन ग्रीन्स	500	0.00
एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड	100000	0.51
पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	15000	0.08
हर्बल खेती को बढ़ावा	4000	0.02
मधुमक्खी पालन पहल	500	0.00
सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना	8100	0.04
जून 2020		
जुलाई से नवंबर (5 महीने) तक पीएमजीके अन्न योजना का विस्तार	82911	0.43
अक्टूबर 2020		
बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर	37000	0.19
एलटीसी वाउचर योजना	28000	0.14
फेस्टिवल एडवांस	8000	0.04
नवम्बर 2020		
आत्मनिर्भर विनिर्माण के लिए बढ़ावा - उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	145980	0.75
आत्मनिर्भर 3.0 के तहत ग्रामीण रोजगार के लिए बढ़ावा	10000	0.05
कोविड सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान - भारतीय टीका विकास	900	0.00
आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (समग्र रूप से 36,000 करोड़ रुपये)	6000	0.03
औद्योगिक अवसंरचना, औद्योगिक प्रोत्साहन और घरेलू रक्षा उपकरण	10200	0.05
कृषि के लिए समर्थन - उर्वरक सब्सिडी	65000	0.33
सभी के लिए आवास - पीएमएवाई-यू	18000	0.09
अवसंरचना के लिए बढ़ावा - एनआईआईएफ ऋण में पीएफ इक्विटी इन्फ्यूजन	6000	0.03
परियोजना निर्यात के लिए बढ़ावा - एक्जिम बैंक के लिए सहायता	3000	0.02

'जीडीपी के लिए 2020-21 के लिए पहले उन्नत अनुमानों यानी 1,94,81,975 रुपये का उपयोग किया गया है।

कर प्रशासन में सुधार

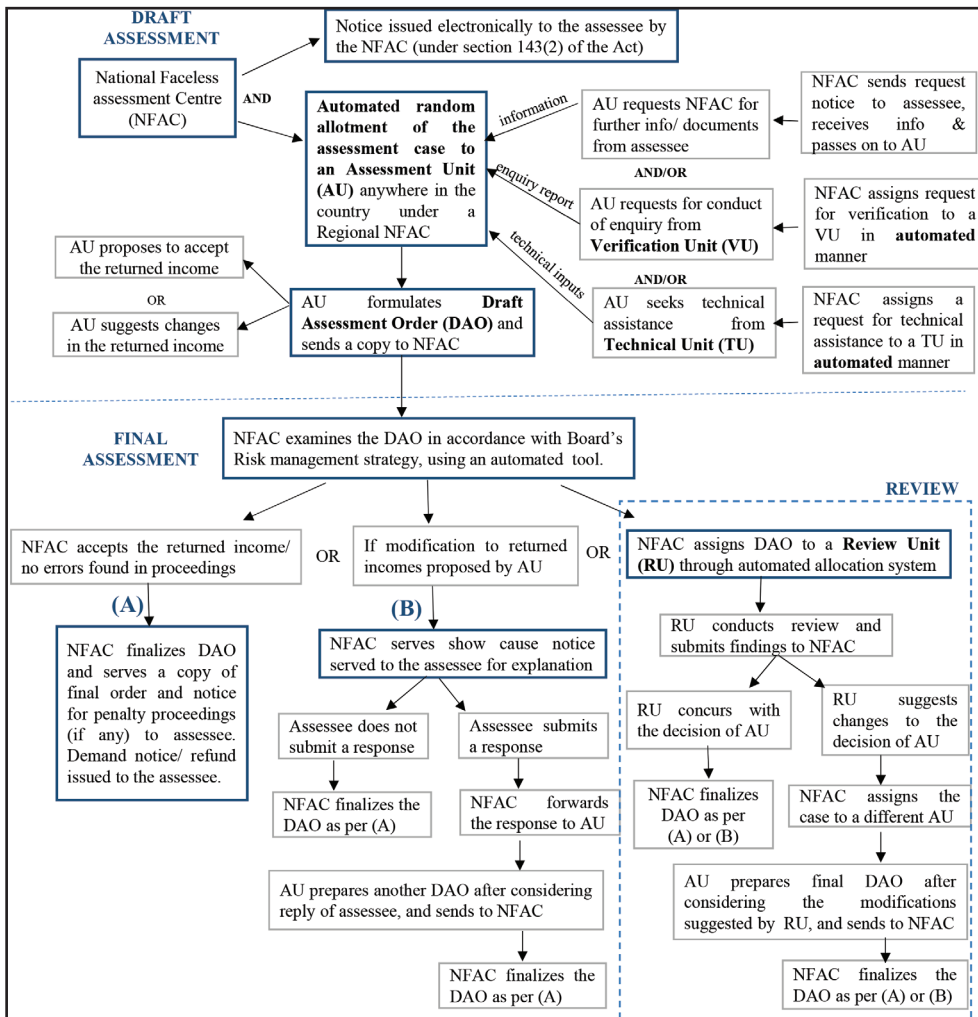
2.18 सरकार ने अधिक पारदर्शी, कुशल और कर-दाता अनुकूल कर प्रशासन के दीर्घकालिक लाभों के उद्देश्य से लगातार सुधार उपायों को अपनाया है। इस दिशा में एक बड़ा कदम 'ऑनरिंग द ऑनरेस्ट' प्लेटफॉर्म की शुरुआत है। 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन- ऑनरिंग द ऑनरेस्ट' का प्लेटफॉर्म अगस्त 2020 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करना और करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच भौतिक इंटरफेस को समाप्त करना था। प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं (i) प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और एआई का उपयोग और (ii) राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में करदाताओं को पहचानना। प्लेटफॉर्म टैक्स प्रशासन सुधारों के 3 स्तंभों पर खड़ा है, यानि कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर। प्लेटफॉर्म को डेटा एनालिटिक्स और एआई, डायनेमिक ज्यूरिस्टिडक्शन, मामलों के स्वचालित अनियमित आवंटन, टीम आधारित मूल्यांकन / समीक्षा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर / समीक्षा के प्रावधान का उपयोग करके सिस्टम के माध्यम से यादृच्छिक चयन जैसे निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है और विभिन्न शहरों में आदेश को अंतिम रूप देना और करदाताओं और आईटी विभाग के बीच भौतिक इंटरफेस को कोर्ड आवश्यकता नहीं है।

फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020

2.19 फेसलेस असेसमेंट योजना, 2019 (जिसे पहले ई-असेसमेंट योजना कहा जाता था और अगस्त 2020 में इसका नाम बदल दिया गया था) इस विचार पर आधारित थी कि आईटी टीमों के मामलों का रैंडम आवंटन और आयकर अधिकारियों और करदाता के बीच आमने-सामने के संपर्क को समाप्त करने से कार्यकुशलता, गैर-विवेकाधीन, असेसमेंट की निष्पक्ष एकल खिड़की प्रणाली का नेतृत्व कर सकती है। 2020 में, फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 के दायरे को योजना के विस्तार में देश भर में लंबित सभी असेसमेंट मामलों को लाकर विस्तृत किया गया और घोषणा की कि योजना के बाहर पारित कोई भी आदेश अमान्य होगा।

2.20 इस योजना ने दिल्ली में एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएसी) स्थापना की, विभाग और करदाता के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु के रूप में जिसकी अगुवाई प्रिंसिपल चीफ कमीशनर ऑफ इंकम टैक्स ने की। करदाता और विभाग से मूल्यांकन/असेसमेंट प्रक्रिया से संबंधित सभी नोटिस या संचार एफएसी के माध्यम से कराई जाती हैं। असेसमेंट की प्रक्रिया को और सुगम बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए, विभिन्न रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हैं जो आकलन करने की शक्ति के साथ निहित हैं। चित्र 7 में फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया का एक योजनाबद्ध आरेख देखा जा सकता है।

चित्र 7: फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया



स्रोत: राजस्व विभाग के इनपुट के आधार पर सर्वेक्षण संकलन।

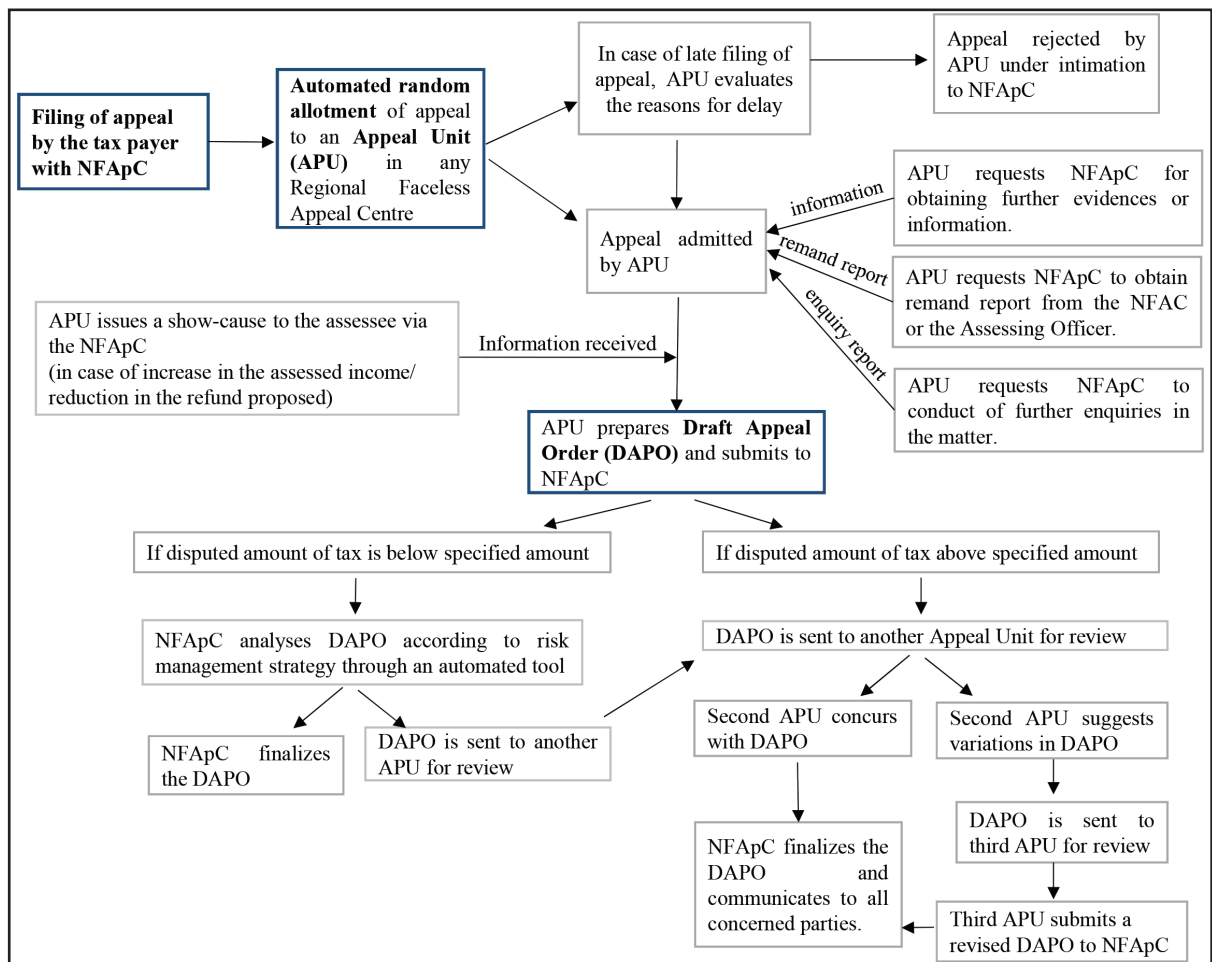
नोट: एफएसी: फेसलेस असेसमेंट सेंटर, एयू: असेसमेंट यूनिट, टीयू: टेक्निकल यूनिट, वीयू: वेरिफिकेशन यूनिट, आरयू: रिव्यू यूनिट, डीएओ: ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर।

फेसलेस अपील योजना 2020

2.21 फेसलेस अपील स्कीम, 2020 के तहत, गंभीर धोखाधड़ी, प्रमुख कर चोरी, संवेदनशील और खोज मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर और काले धन अधिनियम से संबंधित अपीलों के अपवाद के साथ सभी आयकर अपील को फेसलेस इकोसिस्टम के तहत एक फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा।

2.22 यह योजना केंद्रीय स्तर पर ई-अपील की कार्यवाही के संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में एक नेशनल/राष्ट्रीय फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएपीसी) की स्थापना करती है। एनएफएपीसी के तहत ई-अपील की कार्यवाही को सरल बनाने के लिए रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर(एनएफएपीसी) हैं। अपील यूनिट, जिनकी अध्यक्षता एक या अधिक आयुक्त (अपील) करते हैं और उन्हें आरएफएपीसी के अंतर्गत रखा जाता है। एनएफएपीसी करदाता और अंतर्निहित अपील यूनिट्स के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु होगा; और अपील यूनिट्स और नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर /असेसमेंट अधिकारी। सभी आंतरिक और बाह्य संचार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होते और एसेसि या एसेसिंग ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती है। फेसलेस अपील प्रक्रिया का एक योजनाबद्ध आरेख नीचे दिए गए आंकड़े में देखा जा सकता है।

चित्र 8: फेसलेस अपील प्रक्रिया



स्रोत: राजस्व विभाग के इनपुट के आधार पर सर्वेक्षण संकलन।

नोट: एनएफएपीसी: नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, एपीयू: अपील यूनिट, डीएपीओ: ड्राफ्ट अपील ऑर्डर

टैक्सपेयर चार्टर

2.23 'ऑनरिंग द ऑनेस्ट' प्लेटफॉर्म बनाने का तीसरा स्तंभ टैक्सपेयर चार्टर की शुरुवात है। भारत के लिए टैक्सपेयर चार्टर में आयकर विभाग द्वारा प्रतिबद्धताओं और करदाताओं के दायित्व शामिल हैं। टैक्सपेयर चार्टर पर एक विस्तृत चर्चा बॉक्स 2 में देखी जा सकती है।

बॉक्स 2: टैक्सपेयर चार्टर का प्रस्तुतीकरण

परंपरागत रूप से कर प्रशासनों ने कर कानूनों के नियामक और प्रवर्तक के कार्यों को करते हुए करदाता सेवा पर सीमित ध्यान दिया। हालाँकि, कर दाताओं को बेहतर सेवाओं की बढ़ती माँग के कारण, औपचारिक रूप से 'टैक्सपेयर चार्टर्स' प्रकाशित करने या राजस्व निकाय के 'मिशन स्टेटमेंट' में अधिकारियों से अपेक्षित व्यवहार सहित, कर दाताओं के अधिकारों की विश्वव्यापी मान्यता रही है। उदाहरण के लिए, टैक्सपेयरस बिल ऑफ राइट्स(करदाताओं के अधिकार विधेयक) अवधारणा पहली बार 1988 में अमेरिका में पेश की गई थी और करदाताओं के अधिकार विधेयक, जिसने कर कोड में मौजूदा अधिकारों को दस स्पष्ट रूप से परिभाषित मौलिक अधिकारों में वर्गीकृत किया और सभी करदाताओं के लिए लागू किया गया था, को 2014 में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनाया गया था। इसी तरह, कनाडाई करदाताओं के अधिकार विधेयक कनाडा के राजस्व एजेंसी की करदाताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए मई 2007 में 16 करदाताओं के अधिकारों को परिभाषित किया गया था और कर अधिकारियों के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए और राजस्व अधिकारियों से निपटने के दौरान उनके निवारण के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए। यूके सरकार ने 1986 में राजस्व अधिकारियों के साथ करदाता बातचीत से संबंधित अपना पहला चार्टर प्रकाशित किया, और नए प्रकाशन श्योर चार्टर 'को अपनाया, जो स्पष्ट रूप से 2009 में करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है (बाद में 2016 में रिफ्रेश किया गया)।

भारत सरकार द्वारा टैक्सपेयर चार्टर का परिचय 'ऑनरिंग द ऑनरेस्ट' प्लेटफॉर्म के एक भाग के रूप में किया गया है, इस प्रकार, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह करदाता के लिए उचित, विनम्र और उचित उपचार के महत्व पर जोर देता है। टैक्सपेयर चार्टर में आईटी विभाग की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. करदाताओं के लिए विनम्र, निष्पक्ष और उचित व्यवहार।
2. करदाताओं का साथ ईमानदारी का व्यवहार जब तक विभाग के पास अन्यथा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
3. न्यायोचित और निष्पक्ष अपील प्रक्रिया और रिव्यू प्रक्रिया।
4. कानून के तहत कर अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए सटीक और पूरी जानकारी।
5. हर आयकर कार्यवाही में समयबद्ध निर्णय (कानून के तहत निर्धारित समय के अंदर)।
6. कानून के अनुसार देय कर की सही राशि का संग्रह।
7. विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करके करदाता की गोपनीयता का सम्मान, और आवश्यक पूछताछ, परीक्षण या प्रवर्तन कार्रवाई की तुलना में अधिक दखल सुनिश्चित नहीं करता है।
8. जब तक कानून द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक करदाता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी का खुलासा न करके गोपनीयता बनाए रखें।
9. कर अधिकारियों के कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना।
10. करदाता को अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देने का प्रावधान।

11. शिकायत दर्ज करने और इसके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान।
12. न्यायोचित और निष्पक्ष प्रणाली और समयबद्ध तरीके से कर मामलों को हल करना
13. विभाग द्वारा सेवा मानकों को प्रकाशित करना और समय-समय पर कर रिपोर्ट करना।
14. अनुपालन की लागत कम करने के लिए प्रावधान, क्योंकि विधिवत् कर कानून का पालन करते समय अनुपालन की लागत को ध्यान में रखना चाहिए।

चार्टर के तहत निर्दिष्ट करदाताओं के दायित्व हैं:

1. करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी जानकारी का ईमानदारी से खुलासा करे और अपने अनुपालन दायित्वों को पूरा करे।
2. करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह कर कानून के तहत अपने अनुपालन दायित्वों से अवगत हो और जरूरत पड़ने पर विभाग की मदद ले।
3. करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार आवश्यक रिकॉर्ड एकदम सही रखे।
4. करदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कौन सी जानकारी और सबमिशन/प्रस्तुतियाँ दी गयी है।
5. करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह समयबद्ध तरीके से कर कानून के अनुसार सबमिशन/प्रस्तुतियाँ करें।
6. करदाता को समय के अनुसार कानून के अनुसार देय राशि का भुगतान करने की उम्मीद है।

करदाताओं के अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए – एक स्वतंत्र लोकप्रहरी/ओम्बुड्समैन की आवश्यकता करदाताओं के अधिकारों को स्पष्ट रूप से पहचानने के अलावा, करदाताओं के दृष्टिकोण से मुद्दों को उठाने के उद्देश्य से एक समर्पित संस्थान की उपस्थिति प्रणाली में करदाताओं के विश्वास को विकसित करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करता है कि करदाता अपने अधिकारों को समझें और उनके साथ उचित व्यवहार हो। इस प्रकार अगला कदम अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है।

टैक्स ओम्बुड्समैन के साथ भारत का अनुभव

- में अप्रत्यक्ष कर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी अस्तित्व में आया। कर अधिकारी के कामकाज के खिलाफ अन्याय / शिकायतों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी की नियुक्ति सेवारत अधिकारियों से की जाती थी।
- चूंकि ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी का कामकाज दिशानिर्देशों (आयकर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी दिशानिर्देश 2010 और अप्रत्यक्ष कर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी दिशानिर्देश 2011) द्वारा नियंत्रित किया गया था, और विभिन्न कार्यों के साथ लोकपाल को सशक्त बनाने वाला कोई कानून नहीं था, लोकपाल की संस्था अप्रभावी थी क्योंकि लोकपाल के निर्णय प्रकृति में परामर्शी थे। ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी शिकायतकर्ता और कर विभाग के बीच सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से या एक पुरस्कार पारित करके, शिकायतकर्ता द्वारा 5,000 रुपये से अधिक नहीं होने वाले नुकसान के लिए टोकन मुआवजा के साथ शिकायतों का निपटान कर सकता है।
- इसलिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी की संस्थाएं फरवरी 2019 में खत्म कर दी गईं। वर्तमान कर शिकायत निवारण प्रणाली में विभाग के अधिकारियों / आयकर सेवा केंद्रों (एसके), ई-निवारण पोर्टल के नेतृत्व में शिकायत कोशिकाएं शामिल हैं, जो आयकर व्यापार आवेदन और सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) में शिकायत निवारण के लिए एक अलग और समर्पित विंडो है।

स्वतंत्र कर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी के साथ वैश्विक अनुभव

- वैश्विक अनुभव बताता है कि एक स्वतंत्र कर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी वाले देशों ने करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच बेहतर विश्वास के माध्यम से कर प्रशासन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, और जीडीपी अनुपात में एक उच्च औसत कर और कर फाइल करने के लिए कम समय (ओईसीडी 2017) का प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका में ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी जैसे समर्पित निकाय और बेल्जियम और फ्रांस में कर मध्यस्थ कई देशों में कर संबंधी शिकायतों को देखते हैं। ये निकाय कर प्रशासन से स्वतंत्र हैं।
- उदाहरण के लिए, यूएस के पास आईआरएस के भीतर एक स्वतंत्र संगठन है जिसे करदाताओं के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए करदाता अधिवक्ता सेवा/टैक्सपेयर अड्वाकेट सर्विस(टीएसएस) कहा जाता है। यह करदाता अधिकारों की रक्षा करता है और आईआरएस की अखंडता और जवाबदेही में करदाता विश्वास को बढ़ावा देता है; और महत्वपूर्ण स्वतंत्र शक्तियां हैं और सीधे मंत्री को रिपोर्ट करता है। यह राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता के नेतृत्व में है और स्थानीय करदाता अधिवक्ता और निम्न-आय करदाता क्लीनिक के माध्यम से एक स्थानीय उपस्थिति और पहुंच है।
- इसी तरह कनाडा में 2007 में स्थापित टैक्स ओम्बुड्समैन ऑफिस (ओटीओ) को सीआरए द्वारा करदाता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करने और उन्हें संबोधित करने के लिए अनिवार्य है, इस प्रकार, सेवा से संबंधित शिकायतों और प्रणालीगत मुद्दों की स्वतंत्र और उद्देश्य समीक्षाओं के माध्यम से, करदाताओं के लिए अपनी सेवा में सीआरए जवाबदेही और उपचार के लिए काम करना।
- कनाडा, यूएस और यूके के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर, टैक्स ओम्बुड एक्ट (टीएए) के माध्यम से एक स्वतंत्र कर ओम्बुड सिस्टम वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। टैक्सओम्बुड नियुक्त किया जाता है और सीधे वित्त मंत्री को रिपोर्ट करता है, किसी अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन से उत्पन्न किसी सेवा, प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक मामले के बारे में किसी करदाता शिकायत की समीक्षा और पता करने के लिए।

आगे का रास्ता

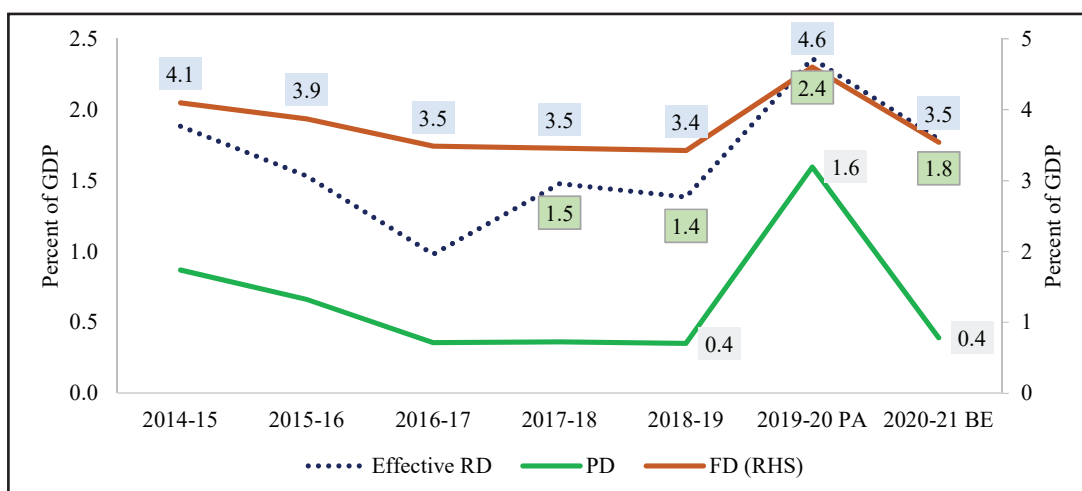
- अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दर्शाता है कि करदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लोकपाल पद्धति आवश्यक है। हालांकि भारत को अनुभव यह है कि संस्थान प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया और इसलिए इसे हटा दिया गया। इसका एक कारण यह हो सकता है कि कर विभाग से समुचित स्वतंत्रता नहीं पई है। इसलिए भारत में शिकायत निवारण की प्रणालियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और करदाता अधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण को शामिल करना है। इस तरह के मामले में हितों के टकराव से बचने के लिए, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करें और फलस्वरूप करदाताओं और संबंधित कर प्राधिकरण के बीच विश्वास का निर्माण करें, यह जरूरी है कि निवारण संगठन के पास पर्याप्त अधिकार हों और कर विभाग से स्वतंत्र हो। इस तरह की एक संस्था कर प्रशासन प्रणाली में जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित करके शॉनरिंग द ऑनरेस्ट 'प्लेटफार्म' को और अधिक सफल बनाएगी।

सरकारी वित्त में प्रवृत्तियां: केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार

केन्द्र सरकार वित्त

2.24 वर्ष 2019-20 के दौरान, आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक सुधारों का अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय प्रभाव था। परिणामस्वरूप 2019-20 के लिए फिस्कल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.6 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो 2019-20 आरई में परिकल्पित राजकोषीय घाटे की तुलना में 0.8 प्रतिशत अधिक था, और 2018-19 में राजकोषीय घाटे की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक था। प्रभावी राजस्व घाटा, जो वर्तमान व्यय पर वर्तमान प्राप्तियों में कमी को पकड़ता है, 2018-19 के सापेक्ष 2019-20 पीए में जीडीपी का 1 प्रतिशत बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है(चित्र 9)।

चित्र 9: घाटे में प्रवृत्तियां



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट एस्टिमेट, पीए: प्रोविशनल ऐक्चुअल्स

एफडी: फिसिकल डेफिसिट; आरडी: रेविन्यू डेफिसिट; प्राथमिक घाटा

2.25 वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार द्वारा अपनाए गए सुधारों के वित्तीय प्रभाव के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने के बाद, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) बजट 2020-21 के साथ प्रस्तुत किए गए वक्तव्य ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.5% पर आंका। केंद्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतक और उनकी विकास दर क्रमशः तालिका 5 और तालिका 6 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 5: केंद्र सरकार के राजकोषीय पैरामीटर

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 PA	2020-21 BE
(लाख करोड़ रुपये में; कोष्टक में आंकड़े जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में हैं)							
राजस्व प्राप्तियां	11.01	11.95	13.74	14.35	15.53	16.82	20.21
	(8.8)	(8.7)	(8.9)	(8.4)	(8.2)	(8.3)	(9)
सकल कर राजस्व	12.45	14.56	17.16	19.19	20.80	20.10	24.23
	(10)	(10.6)	(11.2)	(11.2)	(11)	(9.9)	(10.8)
शुद्ध कर राजस्व	9.04	9.44	11.01	12.42	13.17	13.56	16.36
	(7.2)	(6.9)	(7.2)	(7.3)	(6.9)	(6.7)	(7.3)
गैर-कर राजस्व	1.98	2.51	2.73	1.93	2.36	3.26	3.85
	(1.6)	(1.8)	(1.8)	(1.1)	(1.2)	(1.6)	(1.7)
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	0.51	0.63	0.65	1.16	1.13	0.69	2.25
	(0.4)	(0.5)	(0.4)	(0.7)	(0.6)	(0.3)	(1)
गैर-ऋण प्राप्तियां	11.53	12.58	14.4	15.51	16.66	17.51	22.46
	(9.2)	(9.1)	(9.4)	(9.1)	(8.8)	(8.6)	(10)
कुल व्यय	16.64	17.91	19.75	21.42	23.15	26.86	30.42

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 PA	2020-21 BE
	(13.3)	(13.0)	(12.9)	(12.5)	(12.2)	(13.2)	(13.5)
राजस्व व्यय	14.67	15.38	16.91	18.79	20.07	23.50	26.30
	(11.8)	(11.2)	(11.0)	(11.0)	(10.6)	(11.6)	(11.7)
पूँजीगत व्यय	1.97	2.53	2.85	2.63	3.08	3.37	4.12
	(1.6)	(1.8)	(1.9)	(1.5)	(1.6)	(1.7)	(1.8)
राजकोषीय घाटा	5.11	5.33	5.36	5.91	6.49	9.36	7.96
	(4.1)	(3.9)	(3.5)	(3.5)	(3.4)	(4.6)	(3.5)
राजस्व घाटा	3.66	3.43	3.16	4.44	4.54	6.68	6.09
	(2.9)	(2.5)	(2.1)	(2.6)	(2.4)	(3.3)	(2.7)
प्राथमिक घाटा	1.08	0.91	0.55	0.62	0.67	3.25	0.88
	(0.9)	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(1.6)	(0.4)
मेमो आइटम							
बाजार के मूल्य पर जी.डी.पी.	124.68	137.72	153.62	170.95	189.71	203.40	224.89

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट एस्टिमेंट, पीए: प्रोविशनल ऐक्चुअल

*विनिवेश से प्राप्त आय शामिल है

तालिका 6: केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतक की विकास दर (प्रतिशत में)

आइटम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 PA*	2020-21 BE^
राजस्व प्राप्तियां	8.5	15.0	4.4	8.2	8.3	20.1
सकल कर राजस्व	16.9	17.9	11.8	8.4	-3.4	20.6
शुद्ध कर राजस्व	4.4	16.7	12.8	6.0	2.9	20.7
गैर-कर राजस्व	27.0	8.6	-29.4	22.3	38.4	18.0
गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियां	22.3	3.8	77.0	-2.5	-39.2	227.8
कुल गैर ऋण रसीद	9.1	14.4	7.7	7.4	5.1	28.3
कुल व्यय	7.6	10.3	8.4	8.1	16.0	13.2
राजस्व व्यय	4.8	9.9	11.1	6.8	17.0	11.9
पूँजीगत व्यय	28.6	12.5	-7.5	16.9	9.4	22.4

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट एस्टिमेंट, पीए: प्रोविशनल ऐक्चुअल

*वास्तविक विकास दर की दर 2018-19

^विकास दर की दर 2019-20 पीए

रु इसमें विनिवेश आय शामिल है

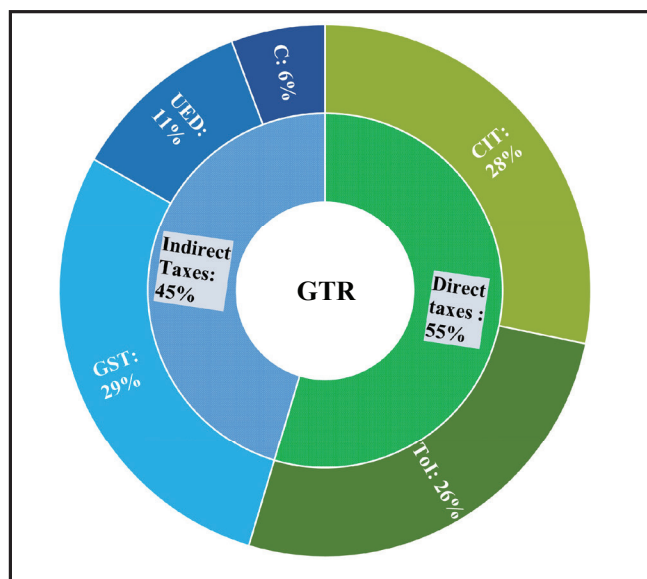
प्राप्तियों में प्रवृत्ति

2.26 केंद्र सरकार की प्राप्तियों को मोटे तौर पर गैर-ऋण और ऋण प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। गैर-ऋण प्राप्तियों में कर और गैर-कर राजस्व शामिल हैं, और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां जैसे ऋणों की वसूली और विनिवेश रसीदें। ऋण प्राप्तियों में ज्यादातर बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल हैं, जिन्हें सरकार भविष्य में चुकाने के लिए बाध्य है।

कर राजस्व

2.27 बजट 2020-21 में सकल कर राजस्व/ग्रास तक्ष रेविन्यू (जीटीआर) 24.23 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जीडीपी का 10.8 प्रतिशत है। यह 2019-20 के संशोधित अनुमानों/रेवाइस्ड एस्टीमेट (आरई) पर 12 प्रतिशत और 2019-20 पीए पर 20.6 प्रतिशत की वृद्धि करता है। प्रत्यक्ष कर, जिसमें मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, जीटीआर का लगभग 55 प्रतिशत गठन करता हैं। इन्हें 2019-20 के सापेक्ष 12.7 प्रतिशत और 2019-20 पीए के सापेक्ष 27.2 प्रतिशत बढ़ने की परिकल्पना की गई थी। दूसरी तरफ, अप्रत्यक्ष कर 2019-20 पीए के मुकाबले 11.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019-20 आरई और 15 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद थी। जीटीआर में विभिन्न करों के योगदान के रूप में परिकल्पित 2020-21 बीई को चित्र 10 में दिखाया गया है।

चित्र 10: 2019-20 बीई में सकल कर राजस्व में करों की संरचना

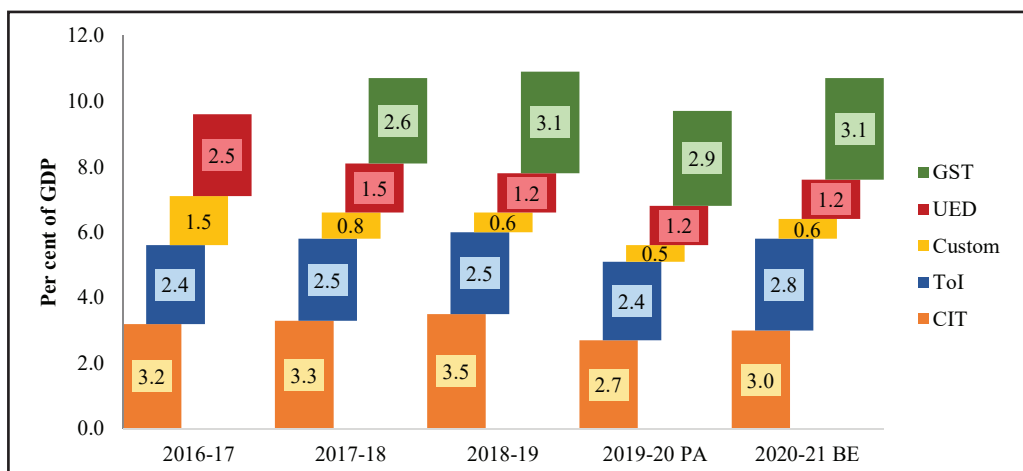


स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

जीटीआर : सकल कर राजस्व/ग्रास तक्न, सीआईटी: निगम कर/कार्पोरेशन टैक्स, टीओएल: निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (एसटीटी सहित),सी: सीमा शुल्क/कस्टम्स, यूईडी: केंद्रीय उत्पाद शुल्क/यूनियन एक्साइस ड्यूटिस, जीएसटी: माल और सेवा कर/गूड्स अँड सर्विस टैक्स

2.28 चित्र 11 में प्रदर्शित जीडीपी के संबंध में प्रमुख करों में प्रवृत्ति दर्शाते हैं कि पिछले वर्षों में देखे गए सुधार के प्रवृत्ति की तुलना में 2019-20 पीए में कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर से प्राप्तियां कम हुई हैं। यह 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि में संतुलन और कॉर्पोरेट टैक्स दर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के कारण है। केंद्र के लिए नेट टैक्स रेवेन्यू के लिए 2020-21 बीई के 16.36 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले, नवंबर 2020 तक वास्तविक प्राप्ति 6.88 लाख करोड़ रुपये है, जो बीई का 42.1 प्रतिशत है।

चित्र 11- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अनंतिम वास्तविक/प्रोविशनल ऐक्चुअलस, सीआईटी: निगम कर/कार्पोरेशन टैक्स, टीओआई: निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (एसटीटी सहित), यूईडी: केंद्रीय उत्पाद शुल्क/यूनियन एक्साइस ड्यूटिस, जीएसटी: माल और सेवा कर/गूड्स अँड सर्विस टैक्स

गैर-कर राजस्व

2.29 गैर-कर राजस्व में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ऋणों पर मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियां, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिशेष सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश और लाभ भारत सरकार को हस्तांतरित, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्तियां और बाहरी अनुदान शामिल हैं। बजट 2020-21 में गैर-कर राजस्व के रूप में 3.85 लाख करोड़ रुपये, जीडीपी का 1.7 प्रतिशत, 2019-20 पीए की तुलना में 0.1 प्रतिशत अंक बढ़ाने का लक्ष्य था। गैर कर राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत लाभांश और लाभ (तालिका 7 का संदर्भ) से उठाया जाने की परिकल्पना की गई है। गैर-कर राजस्व के लिए 2020-21 बीई के रूप में 3.85 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले, नवंबर 2020 तक वास्तविक प्राप्ति बीई का 32.3 प्रतिशत रही है।

तालिका 7: केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व में प्रवृत्तियाँ

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 पीए	2020-21 बीई
	(लाख करोड़ रुपए में)					
ब्याज प्राप्तियां	0.25	0.16	0.14	0.12	0.12	0.11
लाभांश और लाभ	1.12	1.23	0.91	1.13	1.86	1.55
बाहरी अनुदान	0.02	0.01	0.04	0.01	0.00	0.01
अन्य	1.12	1.32	0.84	1.07	1.28	2.15
गैर-कर राजस्व	2.51	2.73	1.93	2.36	3.26	3.85

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

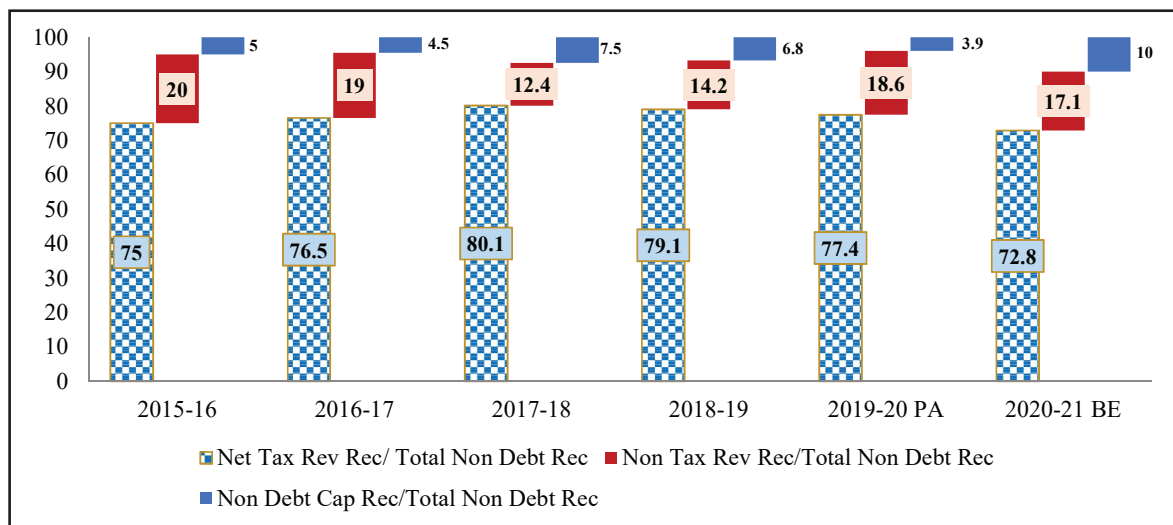
बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अनंतिम वास्तविक/प्रोविशनल ऐक्चुअलस

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

2.30 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋण और अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण प्राप्तियों के कुल पूल में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का योगदान 2018-19 में 6.8 प्रतिशत से घटकर 3.9

प्रतिशत 2019-20 पीए हो गया है, मुख्य रूप से कमी निर्विवाद आय के कारण (चित्र 12)। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों 2.3 लाख करोड़ रुपये आंकी गई हैं जो कि 2020-21 बीई में जीडीपी का 1 प्रतिशत है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का प्रमुख घटक विनिवेश प्राप्तियां हैं जो सरकार द्वारा स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री पर सरकार को प्राप्त होती हैं (रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री सहित)। सरकार ने 2020-21 के अनुसार विनिवेश आय के आधार पर 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की। केंद्र के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के लिए 2020-21 बीई के मुकाबले 2.3 लाख करोड़ रुपये, नवंबर 2020 तक वास्तविक प्राप्ति 0.18 लाख करोड़ रुपये रही है।

चित्र 12: केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों की संरचना



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अनंतिम वास्तविक/प्रोविशनल ऐक्चुअल्स

व्यय में प्रवृत्तियाँ

2.31 व्यय के मोर्चे पर, बजट 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय अनुमानित है, जिसमें 26.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 4.12 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है, जो क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 11.7 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2019-20 पीए पर 2020-21 बीई में कुल व्यय की प्रत्याशित वृद्धि जीडीपी का 0.3 प्रतिशत है, जो राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में जीडीपी के 0.15 प्रतिशत के बराबर है।

2.32 राजस्व व्यय, जो कि कुल व्यय का 87 प्रतिशत है, को 2020-21 बीई में 2019-20 पीए पर 11.9 प्रतिशत बढ़ने की परिकल्पना की गई थी। यह 2018-19 में 2019-20 पीए में राजस्व व्यय की 17 प्रतिशत वृद्धि के सापेक्ष मामूली वृद्धि दर है। ब्याज भुगतान (26 प्रतिशत), रक्षा राजस्व व्यय (9 प्रतिशत), प्रमुख सब्सिडी (10 प्रतिशत), राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान (22 प्रतिशत) और पेंशन (8 प्रतिशत) प्रमुख वस्तुएं हैं राजस्व व्यय जो कुल मिलाकर 2019-20 पीए (तालिका 8) के अनुसार कुल व्यय का लगभग 65% था। रक्षा व्यय के उपयोग और दक्षता में सुधार, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कई पहल अनुलग्नक 3 में देखी जा सकती हैं।

तालिका 8: राजस्व व्यय की प्रमुख वस्तुएँ/ आइटम

आइटम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 च	2020-21 ट
	(लाख करोड़ रुपए में)					
राजस्व व्यय जिनमें से	15.38	16.91	18.79	20.07	23.50	26.30
	(4.8)	(9.9)	(11.1)	(6.8)	(17.0)	(11.9)
a. वेतन (वेतन और भत्ते)	1.45	1.77	1.94	2.11	2.38	2.48
	(7.9)	(22.6)	(9.2)	(9.0)	(12.7)	(4.0)
b. पेंशन	0.97	1.31	1.46	1.60	1.84	2.12
	(3.4)	(35.8)	(10.9)	(9.9)	(14.6)	(15.3)
c. ब्याज भुगतान	4.42	4.81	5.29	5.83	6.11	7.08
	(9.7)	(8.8)	(10.0)	(10.2)	(4.9)	(15.9)
d. प्रमुख सब्सिडी	2.42	2.04	1.91	1.97	2.23	2.28
	(-2.9)	(-15.6)	(-6.3)	(2.9)	(13.4)	(2.1)
e. रक्षा सेवाएँ	1.46	1.65	1.86	1.96	2.08	2.09
	(3.9)	(13.3)	(12.5)	(5.1)	(6.1)	(0.9)

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अनंतिम वास्तविक/प्रोविजनल ऐक्चुअलस कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है

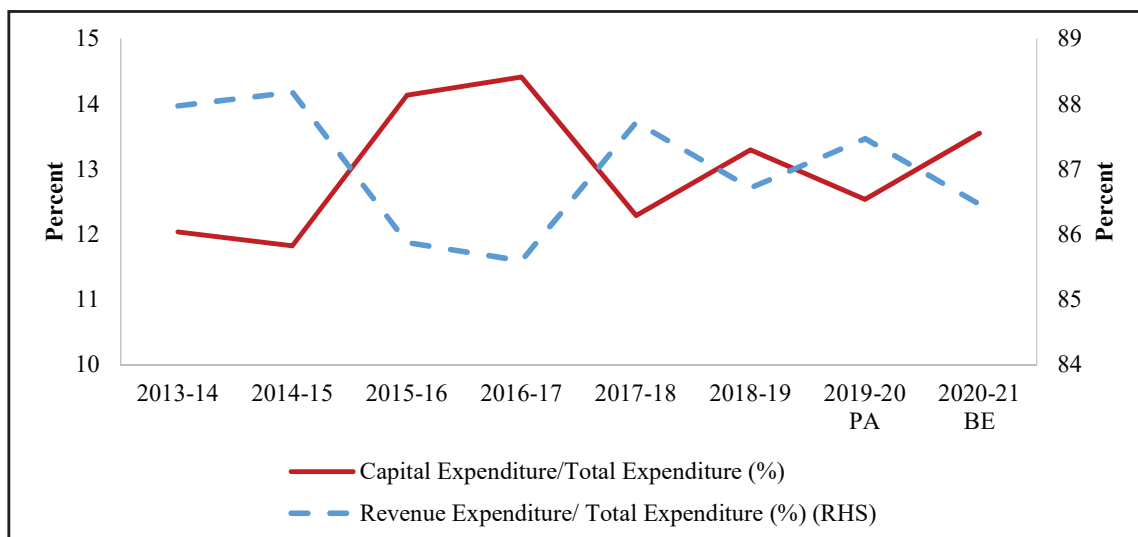
*2019-20 के लिए वेतन (वेतन और भत्ते) का आंकड़ा संशोधित अनुमान/रेवाइस्ड एस्टिमेट (आरई) है।

2.33 राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण अनुपात जैसे वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय, गुण में व्यापक रूप से प्रतिबद्ध है। इसलिए व्यय पुनर्गठन और प्रबंधन उपायों का ध्यान गैर-प्रतिबद्ध घटक जैसे सब्सिडी पर लक्षित है। 2016 में, लगभग 66 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 28 अम्ब्रेला स्कीम में युक्तिसंगत बनाया गया था। इन योजनाओं के चक्र को वित्त आयोग चक्र के साथ को-टर्मिनस भी बनाया गया था, ताकि वित्त आयोग के चक्र पर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए उपलब्ध संसाधनों के प्रवाह पर अधिक स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके।

2.34 प्रमुख सब्सिडी पर खर्च जो कि जीडीपी का 2020-21 बीई में 1.0 प्रतिशत था, 2019-20 पीए पर 2.1 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। 2019-20 पीए में, सरकार के सब्सिडी बिल में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी क्रमशः 7.3 प्रतिशत, 14.9 प्रतिशत और 34.5 प्रतिशत बढ़ी, जो 2018-19 के सापेक्ष थी।

2.35 जीडीपी अनुपात के कम कर के साथ, केंद्र सरकार को राजकोषीय विवेक के दायरे में रहते हुए निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पर्याप्त धन प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए, व्यय की संरचना और गुणवत्ता में सुधार महत्व को मानता है। पिछले कुछ वर्षों में, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी के संदर्भ में मापा गया व्यय की गुणवत्ता औसत स्तर (चित्र 13) पर स्थिर है। यह 2019-20 पीए के मुकाबले 2020-21 बीई में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि से अनुमानित है, जो 2019-20 पीए से अधिक पूंजीगत व्यय में 22.4 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। रक्षा सेवाओं से अलग प्रमुख क्षेत्र, 2020-21 बीई में पूंजीगत व्यय आवंटन के थोक में उद्योग और खनिज, सड़कों और पुलों का निर्माण, संचार सेवाएं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

चित्र 13: कुल व्यय के घटकों में प्रवृत्तियाँ



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अर्न्तम वास्तविक/प्रोविशनल ऐक्चुअल्स, आरई: राजस्व व्यय, केई: पूंजीगत व्यय, टीई: कुल व्यय

2.36 बजटीय खर्च के अलावा, अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) 2016-17 से बुनियादी ढाँचे के निवेश के लिए जुटाए गए हैं। ईबीआर वे वित्तीय देनदारियां/ऋण हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए जाते हैं, जिसके लिए पूरे मूलधन/प्रिन्सपल और ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के बजट से की जाती है। सरकार ने 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान 1.35 लाख करोड़ रुपये का ईबीआर जुटाया है। यह 2020-21 बीई में 49,500 करोड़ रुपये के ईबीआर को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है जो कि जीडीपी का 0.22 प्रतिशत है। फिस्कल डेफिसिट/राजकोषीय घाटे की गणना करते समय इन ईबीआर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि, उन्हें सरकारी ऋण की गणना में माना जाता है।

राज्यों का हस्तांतरण

2.37 केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया है, जो पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, स्थानीय निकायों को अनुदान और वित्तीय वर्ष 2020 के लिए आपदा प्रबंधन अनुदान से संबंधित है। FC-XV ने ग्रांट-इन-एड को 2020-21 के दौरान राज्यों को हस्तांतरण के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपये पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए की सिफारिश की, स्थानीय निकायों और डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स को अनुदान जो कि पुरस्कार वर्ष 2019-20 (तालिका 9) के लिए FC-XIV द्वारा अनुशंसित लगभग 50% अधिक है।

2.38 वर्ष 2020-21 में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में आवंटित 90,000 करोड़ रुपये के कोष में से, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 32.5 प्रतिशत और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए शेष की सिफारिश की गई है। थ्रू-गुट ने अनुदानों की सिफारिश के विपरीत, स्थानीय निकायों के मामले में वर्ष 2020-21 के दौरान स्थानीय निकायों के अनुदान को पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्र के साथ-साथ मंडल / तहसील और जिला / जिलापंचायतों को भी आवंटित किया गया था इसके अलावा पहली बार, दस लाख से ज्यादा शहरों / शहरी समूहों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वित्त आयोग अनुदान भी आवंटित किया गया था।

तालिका 9: FC-XIV (केवल वर्ष 2019-20 के लिए) और FC-XV के दौरान वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसित घटक-अनुदान (रुपये करोड़ में)

क्रमांक	घटक	वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित राशि (FC-XIV अवार्ड अवधि)	वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित राशि (FC-XV अवार्ड अवधि)
(1)	(2)	(3)	(4)
i	पोस्ट डिवायल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट	34,206	74,340
ii	स्थानीय निकाय अनुदान	87,352	90,000
iii	आपदा प्रबंधन अनुदान (संघ साझा)	12,120	34,574
	कुल	1, 33, 678	1, 98,914

2.39 2019-20 के दौरान सकल कर राजस्व संग्रह में गिरावट के कारण, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में 2018-19 (तालिका 10) के सापेक्ष 2019-20 आरई में गिरावट देखी गई है। बजट 2020 - 21 ने राज्यों को कुल हस्तांतरणों में 2019-20 आरई में 5.7 प्रतिशत सेजीडीपी में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तक प्रतिक्षेप की परिकल्पना की।

तालिका 10: राज्यों को हस्तांतरित (लाख करोड़ रुपयों में)

ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
करों में राज्यों की हिस्सेदारी का हस्तांतरण	5.06	6.08	6.73	7.61	6.56	7.84
वित्त आयोग अनुदान	0.85	0.96	0.92	0.94	1.24	1.50
सीएसएस और अन्य हस्तांतरण	2.39	2.77	3.16	3.32	3.80	4.09
राज्यों को कुल हस्तांतरण	8.29	9.81	10.81	11.87	11.60	13.43

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, आरई: संशोधित आकलन

नोट: राज्यों में सभी राज्य शामिल हैं।

केन्द्र सरकार ऋण

2.40 केंद्र सरकार की कुल देनदारियों/लाइअबिलिटीज में भारत के समेकित कोष के खिलाफ अनुबंधित ऋण शामिल हैं, जिसे तकनीकी रूप से सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, साथ ही साथ सार्वजनिक खाते में देयताएं भी शामिल हैं। इन देनदारियों/लाइअबिलिटीज में मौजूदा विनिमय दर पर बाहरी ऋण (वित्तीय वर्ष का अंत) शामिल है, लेकिन एनएसएसएफ से राज्यों की उधारी की सीमा तक एनएसएसएफ की देनदारियों का हिस्सा और एनएसएसएफ से बाहर की सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश, जो केंद्र सरकार के घाटे का वित्तपोषण नहीं करते हैं। मार्च 2020 के अंत में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां 95.07 लाख करोड़ रुपये (तालिका 11 का संदर्भ) थी। इनमें से 90 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण था और शेष 10 प्रतिशत सार्वजनिक खाते की देनदारियों के लिए थे, जिनमें राष्ट्रीय लघु बचत कोष, राज्य भविष्य निधि, आरक्षित निधि और जमा और अन्य खाते शामिल थे।

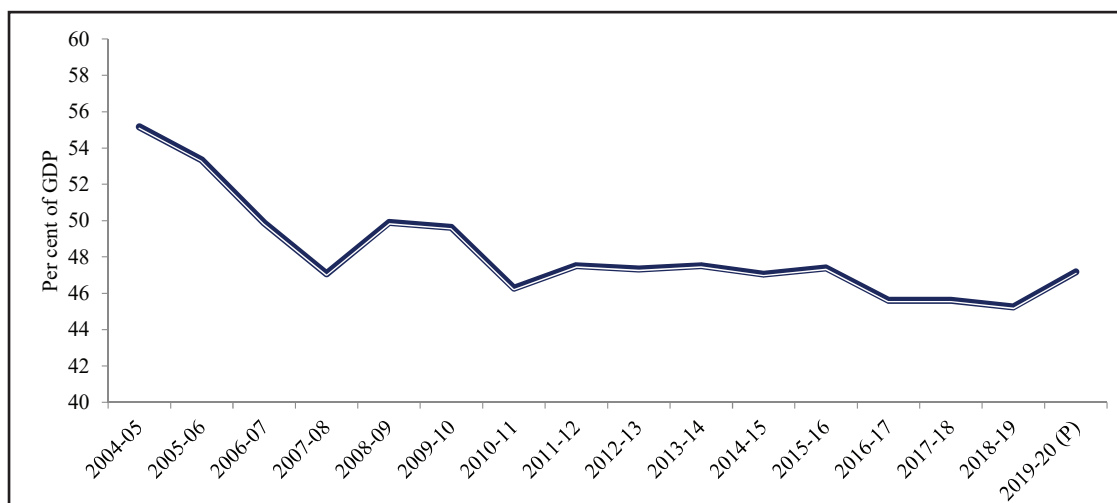
तालिका 11: केंद्र सरकार की ऋण स्थिति (लाख करोड़ रुपयों में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20पी
A. सार्वजनिक ऋण (A1 + A2)	51.05	57.11	61.50	68.84	75.88	86.05
A1. आंतरिक ऋण (a + b)	47.38	53.05	57.42	64.01	70.75	80.20
a. विपणन योग्य प्रतिभूति	43.09	47.28	50.49	55.10	59.69	65.60
b. गैर-विपणन योग्य प्रतिभूति	4.29	5.77	6.93	8.91	11.06	14.60
A2. विदेशी ऋण'	3.66	4.07	4.08	4.83	5.13	5.85
B. लोक लेखा - अन्य देयताएं	7.62	8.16	8.57	9.15	9.96	9.89
C. अतिरिक्त-बजटीय संसाधन	0.00	0.00	0.09	0.24	0.88	1.10
D. कुल देयताएं (A + B + C)	58.66	65.27	70.16	78.23	86.72	95.07

स्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मुद्दे और सार्वजनिक ऋण पर त्रैमासिक रिपोर्ट; पी: प्रोविशनल

2.41 चित्र 14 से पता चलता है कि केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के तुरंत बाद तेजी से गिरावट आई और पिछले दशक के दौरान एक ही स्तर पर कायम रही है।

चित्र 14: केंद्र की ऋण-जीडीपी अनुपात में प्रवृत्ति

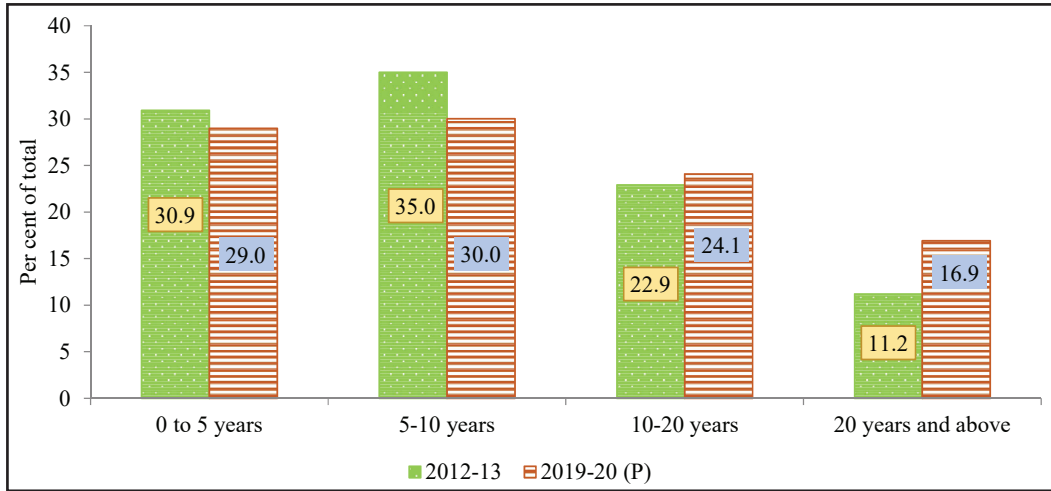


स्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मुद्दे; पीए: प्रोविशनल/अर्न्तितम

2.42 केंद्र सरकार के ऋण को कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की विशेषता है। यह ऋण पोर्टफोलियो में वेदेशी ऋण की कम हिस्सेदारी के कारण है और आधिकारिक स्रोतों से लगभग पूरे बाह्य उधार हैं। इसके अलावा, अधिकांश सार्वजनिक ऋण को भारत के ऋण स्टॉक को ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से अछूता बनाते हुए अनुबंधित ब्याज दर निर्धारित किया गया है। यह ब्याज भुगतान के मामले में बजट के लिए निश्चितता और स्थिरता देता है।

2.43 अन्य मुख्य विशेषता केंद्र सरकार के ऋण की मेचूरिटि प्रोफाइल का क्रमिक विस्तार है (संदर्भ 15 देखें) जो कम रोलओवर जोखिमों को कम करती है। पांच साल से कम समय में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों के अनुपात में हाल के वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2010 के अंत में 9.7 वर्ष से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 10.7 वर्ष हो गई है।

चित्र 15: केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों की बकाया राशि की परिपक्वता प्रोफाइल (कुल का प्रतिशत)

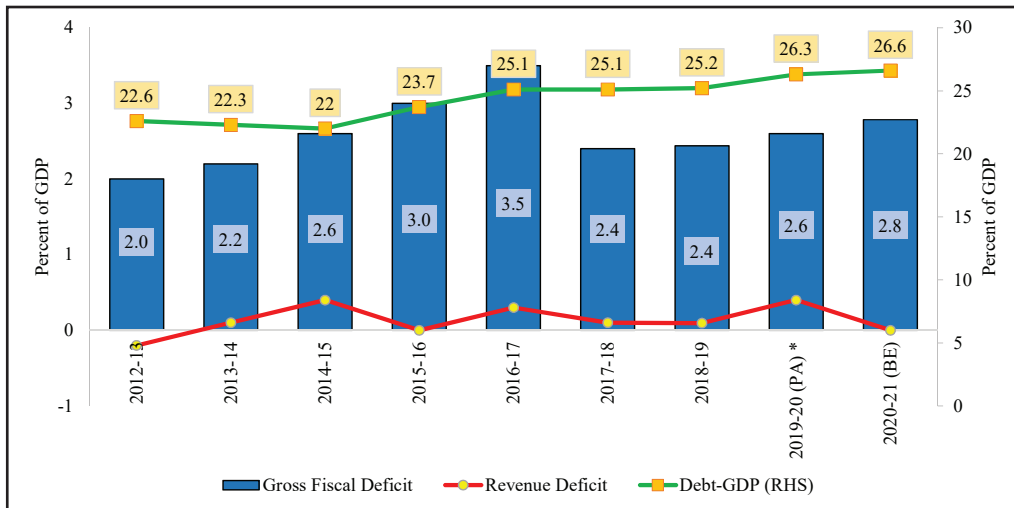


स्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर; सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट; पी: अनंतिम/प्रोविशनल

राज्य वित्त

2.44 राज्यों ने 2020-21 बीई में जीडीपी के समेकित सकल राजकोषीय घाटा 2.8 प्रतिशत के लिए बजट किया था। कोविड-19 के प्रकोप से पहले अपने बजट पेश करने वाले राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमान जीएसडीपी का 2.4 प्रतिशत था, जबकि पोस्ट-लॉकडाउन प्रस्तुत किए गए बजट का औसत 4.6 प्रतिशत जीएसडीपी (स्टेट फाइनेंस पर आरबीआई का अध्ययन) था। चित्र 16 में पिछले 3 वर्षों में सम्मिलित राज्य के लिए राजकोषीय समेकन की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, जिसमें जीडीपी का औसत सकल घरेलू उत्पाद 2.46 प्रतिशत है। राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 के दौरान अनुमानित बजट अनुमान के सापेक्ष जल्द बढ़ने की उम्मीद है।

चित्र 16: राज्यों के प्रमुख घाटे और ऋण संकेतक



स्रोत: आरबीआई का राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन; पीए: प्रोविशनल एक्जुयल्ट्स; बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट

नोट: राज्यों में विधानसभाओं के साथ 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

*सभी राज्यों के लिए आरबीआई द्वारा 2019-20 (पीए) के लिए जीडीएफ और राजस्व घाटे के आंकड़ों का अनुमान है कि शेष 7 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीएजी और 2019-20 बीई के आंकड़ों के साथ उपलब्ध 24 राज्यों के खातों के आंकड़ों का उपयोग करके।

डेफ्ट -टू-जीडीपी के लिए 2019-20 के लिए डेटा संशोधित अनुमान/रेवाइस्ड एस्टिमेट है।

2.45 राज्य सरकारों के 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार, राज्यों के संयुक्त कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व को 2019-20 आरई से अधिक 11.8 प्रतिशत और 12.1 प्रतिशत के आधार पर 2019-20 में बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, जो 2019 में प्रदर्शित विकास से अधिक है। व्यय पक्ष पर, 2020-21 बीई में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्रमशः 8.2 प्रतिशत 11.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ क्रमशः 2019-20 आरई (तालिका 12 का संदर्भ) में परिकल्पित किया गया।

2.46 स्टेट फाइनेंस पर आरबीआई अध्ययन पिछले 3 वर्षों (2017-18 वास्तविक, 2018-19 वास्तविक और 2019-20पीए) के लिए राज्यों में बीई के सापेक्ष वास्तविक पूंजी खर्च में गिरावट को उजागर करता है। पूंजीगत व्यय के उच्च राजकोषीय गुणक प्रभाव को देखते हुए आर्थिक विकास की गति और गुणवत्ता के लिए इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। वास्तव में, चालू वर्ष में, जब राज्य एक विवश राजकोषीय स्थान के साथ महामारी से निपट रहे हैं, तो पूंजीगत व्यय वसूली प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पूंजीगत व्यय पर राज्यों की राजकोषीय नीति का ध्यान केंद्रित करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना की घोषणा की है, जिसकी चर्चा बॉक्स 7 में की गई है।

तालिका 12: राज्यों के राजकोषीय संकेतक

आइटम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
	(लाख करोड़ रुपयों में)					
खुद का कर राजस्व	8.5	9.46	11.3	12.2	13.4	15.0
	(9.0)	(11.3)	(19.5)	(7.5)	(10.3)	(11.8)
खुद का गैर-कर राजस्व	1.5	1.7	1.8	2.2	2.4	2.7
	(7.1)	(14.0)	(5.3)	(21.7)	(9.1)	(12.1)
राजस्व व्यय	18.4	21.22	23.4	26.4	30.8	33.3
	(12.2)	(15.3)	(10.3)	(12.7)	(16.6)	(8.2)
पूंजीगत व्यय	4.2	5.17	4.3	4.9	5.8	6.5
	(40.0)	(23.1)	(-16.6)	(13.0)	(18.7)	(11.8)

स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त: 2020-21 के लिए बजट का अध्ययन,

आरई: रेवाइसड एस्टिमेट; बीई: बजट अनुमान/एस्टिमेट; कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है

नोट: राज्यों में 2017-18 से 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुदुचेरी) भी शामिल हैं

2.47 2019-19 में प्रचलित वृहत आर्थिक परिदृश्य और कम कर संग्रह के मद्देनजर वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य की पात्रता से परे, वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त उधार राशि 0.59 करोड़ रुपये की अनुमति देकर राज्यों को एक बार विशेष छूट दी गई थी।

2.48 वर्ष 2020-21 के लिए 28 राज्यों की नेट उधार लेने की सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपये तय की गई थी, जो कि संबंधित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को FC-XV द्वारा अनुशंसित 3 प्रतिशत है। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के लिए, अभूतपूर्व कोविड-19 को देखते हुए, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी, जिनमें से 1% राज्य स्तरीय सुधार कार्यान्वयन पर सशर्त था। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी को तेजी से आर्थिक सुधार करने की दिशा में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए उठाए गए कई कदम बॉक्स 3 में देखे जा सकते हैं।

बॉक्स 3: केंद्र द्वारा कोविड-19 के समय में राज्यों का समर्थन करने के लिए किए गए उपाय

महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में राकेंद्र सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं केंद्र सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं ये उपाय इस प्रकार हैं:

1. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उधार की बढ़ी हुई सीमा

• आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी, जो कि 4.27 लाख करोड़ रुपये के बराबर थी। राज्यों को अतिरिक्त 2% उधार की अनुमति दी गई, 0.5% उधार की पहली किस्त सभी राज्यों के लिए खुला था। जीएसडीपी का 1% की दूसरी राशि चार विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन थी, जहां प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत था: -

- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;
- व्यापार सुधार करने में आसानी;
- शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; और
- पावर सेक्टर में सुधार

उपर्युक्त सुधारों में से कम से कम 3 को अंतिम रूप देने पर अंतिम 0.5% उधार सशर्त था।

30 दिसंबर 2020 तक, 10 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू की है, 7 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निर्धारित सुधारों को पूरा किया है, और 2 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं। कुल अतिरिक्त उधार अनुमति उन राज्यों को जारी की गई है जिन्होंने सुधार किए हैं, जो 51,682 करोड़ रुपये है।

2. जीएसटी राजस्व में नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा

• वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष विंडो के तहत ऋण के मुद्दे के माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को उधार लेने का एक विकल्प दिया था जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया था (विकल्प 1), या बाजार ऋण (विकल्प 2) के मुद्दे के माध्यम से पूरी कमी को उठाए। सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश विधायिका के साथ विकल्प 1 के लिए जाने का निर्णय लिया, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित बैंक-टू-बैंक उधार शामिल है, और जीएसटी मुआवजे के तहत प्रवाह के समान संसाधनों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करेगा। 23 अक्टूबर, 2020 से 1.1 लाख करोड़ रुपये की विशेष विंडो का परिचालन किया गया है और भारत सरकार ने पहले ही पांच किस्तों में राज्यों की ओर से 54,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली है और इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पारित किया है।

• विकल्प 1 की शर्तों के तहत, राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमत 2% अतिरिक्त उधारी में से जीएसडीपी की 0.5 प्रतिशत की अंतिम किस्त उधार लेने की बिना शर्त अनुमति प्राप्त करने का भी अधिकार है। यह जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक विशेष विंडो से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त जुटाने की राशि है।

• इसके अतिरिक्त, विकल्प 1 का चयन करने वाले राज्य अगले वित्त वर्ष के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमत अतिरिक्त उधार की छत को आगे ले जाने में सक्षम होंगे, जिससे प्रत्येक की पहली और अंतिम किस्तों को 0.5 प्रतिशत बिना शर्त के आगे बढ़ाया जा सके; यदि राज्यों द्वारा इस वर्ष पहले से निर्धारित तारीखों के भीतर सुधार मानदंड पूरा करते हैं तो सुधार से जुड़े अंशों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

- उच्च उधारी लागत से राज्यों को बचाने की दृष्टि से, केंद्र विशेष उधारी खिड़की के लिए लागत को सरकारी सिक्योरिटी(जी-सेक) उपज के करीब या उसके नजदीक रखने का प्रयास करेगा, और लागत अधिक होने की स्थिति में, यह सब्सिडी के माध्यम से, सरकारी सिक्योरिटी(जी-सेक) और औसतन 50 बीपीएस तक के राज्य विकास ऋण पैदावार के बीच का अंतर वहन करेगा। विशेष विंडो के तहत उधार पर ब्याज का भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर/सैस के रूप में और जब यह संक्रमण की अवधि के अंत तक उठता है। संक्रमण अवधि के बाद, मूलधन और ब्याज का भुगतान उपकर/सैस की आय से भी किया जाएगा, जो कि आवश्यक अवधि के लिए संक्रमण अवधि से परे उपकर/सैस बढ़ाकर किया जा सकता है। राज्य को ऋण की व्यवस्था करने या किसी अन्य स्रोत से इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना

- वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कर राजस्व में कमी के कारण राज्य सरकारों द्वारा सामना किए गए राजकोषीय वातावरण को देखते हुए, श्रृंखलागत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, जो कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- इस योजना में आठ उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 1600 करोड़ रुपये (प्रत्येक के लिए 200 करोड़) का ऋण शामिल है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए 900 करोड़ रुपये का ऋण (प्रत्येक के लिए 450 करोड़ रुपये), शेष राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये (15 वें वित्त आयोग विचलन के अनुसार), और उन राज्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपये, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उधार प्रावधान के तहत उल्लिखित 4 सुधारों में से कम से कम 3 को पूरा करते हैं। ऋण राशि का उपयोग नई या चल रही पूंजी परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, जिन्हें इस तरह की परियोजनाओं पर धन और / या ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का निपटान करना चाहिए।
- 12 दिसंबर 2020 तक, 27 राज्यों के लिए 9,879.61 करोड़ रुपये की पूंजी व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

4. एसडीआरएफ

- एसडीआरएफ के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बार के विशेष वितरण के माध्यम से कोविड -19 को एक अधिसूचित आपदा के रूप में माना था। महामारी से निपटने के लिए राज्यों को मजबूत करने के लिए, केंद्र ने अप्रैल 2020 में राज्य सरकारों को 11,092 करोड़ रुपये की एसडीआरएफ की पहली किस्त जारी की थी। सितंबर 2020 में, एसडीआरएफ को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च करने की राज्यों की सीमा 50% तक बढ़ाई गई थी, ताकि उन्हें कोविड-19 के नियंत्रण उपायों में समर्थन देने के लिए, क्वारंटाइन, संपल संग्रह और स्क्रीनिंग के उपायों सहित; और कोविड -19 की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों/प्रयोगशालाओं की खरीद।

स्रोत: पीआईबी

सामान्य सरकारी वित्त

2.49 सामान्य सरकार के वित्त पूरे क्षेत्र के रूप में सरकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का अवलोकन देते हैं। चित्र 13 सामान्य सरकारी ऋणों और पिछले कुछ वर्षों में घाटे को दर्शाता है। जीडीपी के अनुपात में सामान्य सरकार की देनदारियां पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती हैं। 2020-21 बीई में, सामान्य सरकार ने 2019-20 आरई से अधिक घाटे में कमी के लिए बजट दिया था। हालांकि वैश्विक महामारी के प्रकोप के मद्देनजर, सामान्य सरकार (केंद्र के साथ राज्य) को राजस्व में कमी और उच्च व्यय आवश्यकताओं के कारण वित्तीय घाटा दर्ज करने की उम्मीद है। जैसा कि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए 2020-21 के लिए बढ़ाए गए उधार प्रावधानों से संकेत मिलता है, सामान्य सरकार की देनदारियों में वृद्धि की उम्मीद है। राजकोषीय समेकन के मार्ग से यह विचलन हालांकि क्षणिक हो सकता है क्योंकि राजकोषीय संकेतक अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ पलटाव कर सकते हैं। सरकारी ऋण का मध्यम और दीर्घकालिक प्रक्षेपवक्र ऋण स्थिरता गणना पर निर्भर करेगा। एक अधिक नकारात्मक ब्याज दर वृद्धि अंतर जीडीपी के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार के ऋण की आधारशिला रखता है (तालिका 13)। ऋण स्थिरता की गतिशीलता पर विस्तृत चर्चा वॉल्यूम 1 के अध्याय 2 में देखी जा सकती है।

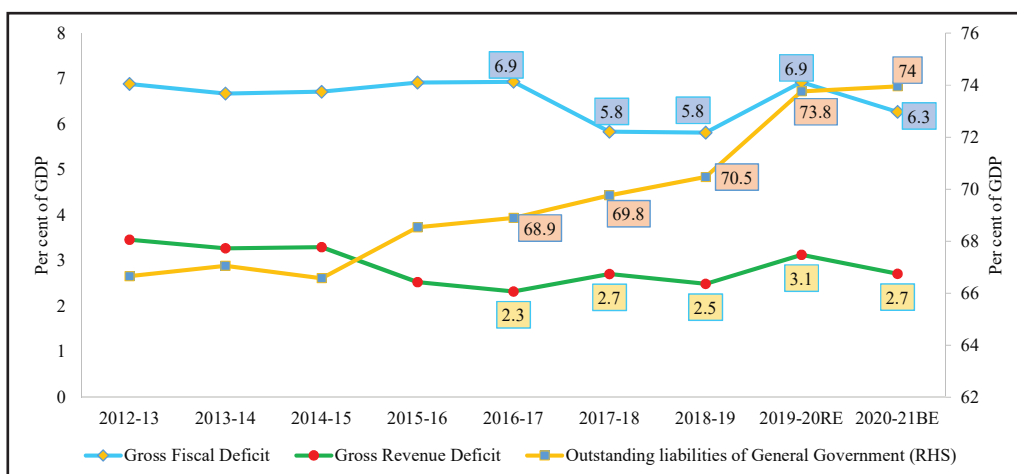
तालिका 13: ब्याज दर-विकास अंतर/ग्रोथ डिफरेंशियल और सामान्य सरकार ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद में प्रवृत्ति

वर्ष	नाममात्र ब्याज दर (i)	नाममात्र की विकास दर (γ)	ब्याज दर-वृद्धि अंतर ($i-\gamma$)	सामान्य सरकारी ऋण-से-जीडीपी
2011-12	8.52	15.74	-7.2	67.4
2012-13	8.36	13.82	-5.5	66.7
2013-14	8.45	12.97	-4.5	67.1
2014-15	8.51	10.99	-2.5	66.6
2015-16	7.89	10.46	-2.6	68.5
2016-17	7.16	11.76	-4.6	68.9
2017-18	6.97	11.09	-4.1	69.8
2018-19	7.78	10.95	-3.2	70.5
2019-20	6.85	7.21	-0.4	73.8

स्रोत: आरबीआई, एमओ एसपीआई/सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नोट: नाममात्र ब्याज दर केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों पर भारत औसत ब्याज दर है

चित्र 17: सामान्य सरकारी ऋण और घाटे में प्रवृत्ति (सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत के रूप में)



स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सांख्यिकी पुस्तिका;

बीई: बजट अनुमान/एस्टिमेट; आरई: रेवाइसड एस्टिमेट

2019-20 आरई, 2019-20 के लिए जीडीपी का प्रोविजनल एस्टिमेट यानी 20339849 रुपये का उपयोग किया गया है

आउटलुक

2.50 वर्ष 2020-21 राजकोषीय दृष्टिकोण से एक कठिन वर्ष रहा है। अप्रैल से नवंबर 2020 के लिए उपलब्ध प्रवृत्तियों के आधार पर, वर्ष के दौरान वित्तीय गिरावट होने की संभावना है। सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया मांग और आपूर्ति पक्ष की नीतियों का एक संयोजन है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के दायरे में महामारी के झटके के खिलाफ कुशन है और बाद में आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हुए, कुल मांग में सुधार को बनाए रखने के लिए, यह उम्मीद की जाती है कि सरकार को विस्तारक राजकोषीय रुख के साथ जारी रखना पड़ सकता है। वर्ष के दौरान पेश किए गए विभिन्न प्रमुख सुधारों के साथ-साथ व्यय समर्थन से मध्यम अवधि के विकास के लिए आवश्यक गति प्रदान करने की संभावना है। भारत द्वारा अपनाए गए कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण से यदि आवश्यक हो तो राजकोषीय आवेग को बनाए रखने के लिए जगह मिलती है। वृद्धि की वसूली मध्यम अवधि में आय के संग्रह को आसान बनाएगी, और इस तरह एक स्थायी राजकोषीय मार्ग को सक्षम बनाएगी। इसके अलावा आने वाले महीनों में पन्द्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी करने से केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय नीति की रणनीति का रोडमैप तैयार होगा।

अध्याय एक नजर में

- कोविड-19 महामारी के प्रभाव से सुगम अर्थव्यवस्था सुधार की सुविधा के लिए भारत सरकार ने कई देशों द्वारा अपनाई गई फ्रंड-लोडेड प्रोत्साहन पैकेज के विपरीत परिस्थितियों के लिए एक अनुकूलतम दृष्टिकोण अपनाया।
- 2020-21 में व्यय नीति उभरती हुई जरूरतों की परिस्थितियों के अनुसार बदली है। आरंभ में इसका उद्देश्य वंचित समूहों की सहायता करना था परंतु जब लॉकडाउन लगाया गया तो यह पूंजीगत खर्चों के माध्यम से समग्र मांग को फिर से मजबूत करने के लिए उन्मुख हुआ।
- पिछले कुछ माह में अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण मासिक राजस्व संग्रह में तेजी देखी गई है। मासिक जीएसटी संग्रह ने पिछले तीन माह में लगातार एक लाख करोड़ रुपये का आँकड़ा पार किया है, जो दिसंबर 2020 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।
- कर व्यवस्था में सुधार ने पारदर्शी प्रक्रिया, जबावदेही तथा महत्वपूर्ण रूप से करदाता का कर प्राधिकरण से अच्छे अनुभव को निर्धारित किया है जिसके परिणामस्वरूप कर अनुपालना को प्रोत्साहन मिला है। वैश्विक महामारी प्रकोप मद्देनजर सरकार को राजस्व में कमी तथा उच्च व्यय आवश्यकताओं के कारण (केंद्रीय/राज्य) वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय कमी का अनुमान है।
- हालाँकि, दीर्घावधि स्थिरता, शासकीय ऋण की ब्याज लागत के सापेक्ष विकास को पुनर्जीवित करने पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1: 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के लिए सीबीडीटी की प्रतिक्रिया

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप के कारण क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर, भारत सरकार ने व्यवसायों और व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपाय किए हैं:

- (i) कराधान और अन्य कानून (रियायत और कुछ प्रावधानों के संशोधन) अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया गया है जिसके तहत:
 - (a) कराधान कानूनों के तहत अनुपालन और वैधानिक कार्यों के लिए विभिन्न समय सीमाएं, अन्य संबंधित कानून और इन अधिनियमों के तहत निर्धारित / जारी किए गए नियमों या अधिसूचनाओं को बढ़ाया गया है;
 - (b) 20.03.2020 से 29.06.2020 तक के भुगतान के लिए आयकर (उदाहरण के लिए अग्रिम कर, TDS, TCS), समान लेन-देन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी), कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (सीटीटी) के भुगतान में देरी के लिए ब्याज दर 9% प्रति वर्ष से कम (0.75% प्रति माह) लिया जाएगा, यदि भुगतान 30.06.2020 द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, इन गैर-भुगतानों के लिए कोई जुर्माना / अभियोग शुरू नहीं किया जाएगा।
 - (c) अतिरिक्त कर के भुगतान के बिना 31.03.2020 से 31.12.2020 तक डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के आवेदन की तिथि का विस्तार [अधिनियम से संबंधित लंबित विवादों के समाधान के लिए अधिनियमित]। इसके अलावा, अतिरिक्त राशि के बिना कर के भुगतान की नियत तिथि 31.03.2021 तक बढ़ा दी गई है;
 - (d) अधिनियम के 100% कटौती यू / एस 80 जी के लिए पात्र होने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) को किया गया दान। उक्त कोष की आय को भी छूट दी गई है।
 - (e) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और साथ ही रिवाइज्ड इंकम रिटर्न दर्ज करने का समय (अय 2019-20 से प्रासंगिक) 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है;
 - (f) वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21 के लिए प्रासंगिक) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 और 31 जनवरी, 2021 तक कंपनियों आदि के लिए विस्तारित की गई। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख भी मौजूदा 30 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है;
 - (g) करदाताओं के मामले में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की तिथि, जिसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स देयता रुपये 1 लाख तक है, को 31 दिसंबर, 2020 (नॉन-ऑडिट योग्य मामलों के लिए) और 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है
 - (h) अधिनियम के अध्याय टप-ठ के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश / भुगतान करने की तारीख को भी 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है;
 - (i) अधिनियम की धारा 54 से 54जीबी के तहत पूंजीगत लाभ के संबंध में निवेश / निर्माण / खरीद / कटौती करने की तारीख को 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है;
 - (j) अधिनियम की धारा 10 ए के तहत कटौती का दावा करने वाली सेज इकाइयों के लिए परिचालन शुरू करने की तारीख को भी 30 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिन्हें 31 मार्च, 2020 तक आवश्यक मंजूरी मिल गई है;
 - (k) वित्त वर्ष 2019-20 के संबंध में टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट प्रस्तुत करने और टीडीएस / टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा क्रमशः 31 जुलाई, 2020 और 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी गई है;

- (1) अधिकारियों द्वारा नोटिस देने या आदेश जारी करने की तिथि और विभिन्न प्रत्यक्ष करों और बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालनों को पारित करने की आवश्यकता है जिन्हें 31 दिसंबर, 2020 तक पारित / जारी / किया जाना आवश्यक है, इसे 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
- (m) आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को भी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दि गयी है;
- (n) 20 मार्च, 2020 से 30 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान आने वाले विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत अनुपालन की तारीखों को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
- (o) भारत में एक आवासी के मामले में अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट, नियत तारीख (विस्तार से पहले) के तहत अधिनियम की धारा 140I के तहत उसके द्वारा भुगतान किए गए करों को अग्रिम कर माना जाएगा।
- (p) अधिनियम की धारा 10 (23C), 12II, 35 और 80जी के तहत कुछ संस्थाओं के अनुमोदन / पंजीकरण / अधिसूचना के लिए नई प्रक्रिया का कार्यान्वयन 01.06.2020 से 01.04.2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- (q) आवासी को निर्दिष्ट गैर-वेतन भुगतान के लिए टीडीएस दर और निर्दिष्ट टीसीएस दरों को 14.05.2020 से 31.03.2021 तक निर्दिष्ट दरों के 25 प्रतिशत से कम किया जाना है। इस उपाय से 50,000 करोड़ रुपये की नकदी मिलेगी।
- (ii) आयकर नियमावली, 1962 के फॉर्म 3सीडी में जीएएआर अनुपालन और जीएसटी की रिपोर्टिंग के संबंध में 2020 के दिनांक 24.04.2020 के परिपत्र संख्या 10 के माध्यम से, खंड 30 सी और खंड 44 की प्रयोज्यता को 31.03.2021 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) 2020 के सर्कुलर नंबर 11 दिनांक 8/5/2020 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अधिनियम की धारा 6 के तहत भारत (कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के कारण भारत में रुकना लंबे समय तक रहा) की यात्रा पर एक व्यक्ति के निवास के निर्धारण के लिए, इतनी लंबी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, एक प्रेस रिलीस भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रेजिडेंसी के निर्धारण के लिए अवधि के बहिष्करण के लिए परिपत्र को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के सामान्यीकरण/ बहाली के आधार पर नियत समय में जारी किया जाएगा।
- (iv) नियोक्ता / डीडीओ के प्रमाण पत्र के आधार पर नियोक्ता / डीडीओ के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रथम नमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) को किए गए दान के लिए कटौती के दावे के लिए सरल प्रक्रिया।
- (v) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दायर कम / शून्य टीडीएस / टीसीएस के लिए लंबित आवेदन के निपटान के लिए उदार और सरलीकृत प्रक्रिया।
- (vi) एलटीसी के लिए यात्रा के बदले में निर्दिष्ट खर्च के लिए कर छूट की घोषणा की गई है।
- (vii) रियल-एस्टेट डेवलपर द्वारा निर्दिष्ट आवासीय इकाइयों के हस्तांतरण के लिए स्टॉप ड्यूटी मूल्य के विश्वास /डीमिंग के लिए थ्रेसहोल्ड को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

अनुलग्नक 2: 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के लिए सीबीआईसी की प्रतिक्रिया

2020-21 के दौरान कोविड-19 के जवाब में सीबीआईसी द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

सीमाशुल्क

- i. 24*7 सीमा शुल्क निकासी/क्लियरेंस सुविधा किसी भी आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से बचने के लिए सभी कस्टम संरचनाओं पर लागू की गई है

- ii. एक्सिम ट्रेड के लिए नोवेल कोरोनावायरस हेल्प डेस्क- एक्सिम व्यापार के लिए एक समर्पित सिंगल विंडो कोविड-19 हेल्पडेस्क सीबीआईसी वेबसाइट पर बनाया गया है ताकि आयातक / निर्यातक द्वारा जारी किए गए मुद्दे के त्वरित समाधान की सुविधा मिल सके।
- iii. कोविड-16 संकट के बीच सीमा शुल्क मंजूरी की सुविधा के लिए भारत के प्रत्येक सीमा शुल्क क्षेत्र में नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।
- iv. अखिल भारतीय आधार पर स्वचालित क्लियरेंस का कार्यान्वयन - मानव इंटरफेस को कम करने और सामाजिक दूरी को बढ़ाने के लिए, ओओसी (आउट ऑफ चार्ज) काम, अब तक एक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसे ईडीआई प्रणाली को सौंपा गया है। आयात खेपों की मशीन-आधारित स्वचालित रिलीज को पूरे भारत में 05.03.2020 को लॉन्च किया गया है।
- v. लॉक-डाउन अवधि के दौरान स्टैम्प पेपर की अनुपलब्धता के कारण आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए, विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क बॉन्ड की आवश्यकता को दूर कर दिया गया है। व्यापारी बांड के बदले सादे कागज पर उपक्रम जमा कर सकते हैं।
- vi. कोविड-19 से लड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण सामानों की जैसे कि चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स, टेस्टिंग/परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण /पीपीई(पर्सनल प्रोटेक्टिव किट) प्राथमिकता वाली निकासी सुनिश्चित की जाती है। इन वस्तुओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों- वेंटिलेटर, मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, परीक्षण किट और इनपुट के लिए बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकरण से छूट दी गई है।
- vii. मूल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, अधिमान्य उपचार का विस्तार करते हुए भारत के व्यापार समझौतों के तहत माल की अंतिम निकासी।
- viii. पेपरलेस कस्टम्स/सीमाशुल्क - कस्टम ब्रोकर्स / आयातकों के लिए पीडीएफ आधारित गेट-पास और ओओसी कॉपी ऑफ बिल एंट्री का इलेक्ट्रॉनिक संचार। आयातकों के इलेक्ट्रॉनिक संचार को सक्षम करना, प्रवेश का बिल और आयातकों / कस्टम ब्रोकर्स को गेट-पास करना।
- ix. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और भौतिक उपस्थिति को कम करने के लिए आयोजित की जा सकती है।
 - a. विशेष वापसी और ड्रॉबैक निपटान ड्राइव। व्यावसायिक संस्थाओं, विशेषकर एमएसएमई को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सभी लंबित सीमा शुल्क वापसी और कमियों के दावों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए ड्राइव।
 - b. आईजीएसटी एसबी005 वैकल्पिक तंत्र में निर्यात-विस्तार पर रिफंड करता है। 31.12.2019 तक की तारीख के साथ शिपिंग बिल के लिए सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में एसबी005 त्रुटि सुधार की सुविधा का विस्तार।
 - c. लोकडाउन के दौरान आईसीडी / सीएफएस / पोर्ट्स / टर्मिनल ऑपरेटर्स द्वारा लगाए गए डिमर्जेज/ विलम्बन शुल्क पर छूट। जोनल कस्टम्स के मुख्य आयुक्तों ने स्थानीय संरक्षकों (इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों) को लोकडाउन अवधि के दौरान डिमर्जेज शुल्क से छूट देने के लिए कहा है।
 - d. कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में छूट प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश है या वहाँ से जुड़े मामलों के लिए या आकस्मिक रूप से अपील दायर करने के लिए समय सीमा, रिटर्न प्रस्तुत करने, या सीमा शुल्क अधिनियम या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत किसी भी अन्य अनुपालन, जो 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक समाप्त हो रहे थे, को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
- x. महामारी से जूझ रहे अन्य देशों के लिए एक राहत उपाय के रूप में, महत्वपूर्ण दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) आदि के विशिष्ट निर्यात शिपमेंट्स को सीमाओं पर

कस्टम्स द्वारा सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाया गया है। इनमें से कुछ शिपमेंट भारत सरकार से दान हैं।

- xi. ईमेल के जरिये मांग के आधार पर, लॉकडाउन अवधि के दौरान घर से काम की सुविधा के लिए कस्टम्स द्वारा भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कर्मचारियों के निवास स्थान से कस्टम्स द्वारा द्वारा हस्तांतरित किए जाने के लिए कंप्यूटर और संबंधित सामान की अनुमति दी गई है।
- xii. सीबीआईसी ने अन्य मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय किया कि कस्टम्स को लॉकडाउन अवधि के दौरान एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया है, जिसने सभी कस्टम् स्टेशनों पर सुचारू संचालन की अनुमति दी है। उपर्युक्त के अनुरूप, आगे के निर्देशों को सीमा शुल्क दलालों और ट्रांसपोर्टर्स की आवाजाही की अनुमति जारी की गई, और लॉक डाउन अवधि के दौरान गोदामों के कामकाज की अनुमति दी गई।
- xiii. सीबीआईसी ने अन्य मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय किया कि सीमा शुल्क को लॉक डाउन अवधि के दौरान एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया है, जिसने सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर सुचारू संचालन की अनुमति दी है। उपरोक्त के अनुरूप, आगे के निर्देशों को कस्टम्स दलालों और ट्रांसपोर्टर्स की आवाजाही की अनुमति जारी की गई, और लॉक डाउन पीरियड 1 के दौरान गोदामों के कामकाज की अनुमति दी गई। सभी कस्टम संरचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों से कार्गो से निपटने में अधिक संवेदनशीलता दिखाने के लिए कहा गया है, आयात घोषणाओं को दर्ज करने में देरी की निंदा करें और वास्तविक मामलों में देर से फाइलिंग शुल्क माफ करें।
- xiv. प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निकासी में विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे यात्रियों के लिए हवाई अड्डों, बंदरगाह टर्मिनलों और भूमि कस्टम् स्टेशनों पर अलग-अलग चौकल बनाए गए थे। सीमा शुल्क अधिकारियों ने मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के निर्देशों का सख्ती से पालन किया।
- xv. सीबीआईसी ने बंदरगाह और हवाई अड्डे के अधिकारियों और अन्य संरक्षकों के साथ समन्वय किया है ताकि यह देखा जा सके कि सीमा शुल्क क्षेत्र में एक्सिम कार्गो के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

B. जीएसटी

- i. कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं को राहत देने के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं
 - a) अपील दायर करने, रिटर्न प्रस्तुत करने या जीएसटी अधिनियम के तहत किसी अन्य अनुपालन के लिए समय सीमा अध्यादेश के अनुसार बढ़ा दी गई है।
 - b) मई 2020 में महीने में आपूर्ति के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख का विस्तार।
 - c) अनुपालन की नियत तारीख का विस्तार जो "20.03.2020 से 29.06.2020" की अवधि के दौरान 30.06.2020 तक और ई-वे बिल की वैधता का विस्तार करने के लिए होता है।
 - d) मार्च, 2020 तक समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 प्रस्तुत करने की नियत तारीख का विस्तार, 07.07.2020 तक और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 को दाखिल करने का समय 15.07.2020 तक है।
 - e) फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए देर से शुल्क की सशर्त माफी।
 - f) फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न देने में देरी के लिए विलंब शुल्क की सशर्त माफी।
 - g) फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए ब्याज दर में कमी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30.06.2020 तक कंपोजीशन स्कीम चुनने की अनुमति देने के लिए सीजीएसटी नियम (चौथा संशोधन) में संशोधन और नियम 36 (4) में संचयी आवेदन की अनुमति देने के लिए

- ii. विशेष जीएसटी रिफंड डिस्पोजल ड्राइव - लंबित जीएसटी और आईजीएसटी रिफंड के दावों में तेजी लाने के लिए निर्णय का कार्यान्वयन
- iii. सीमा शुल्क/कस्टम अधिनियम, 1962 के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने और भौतिक उपस्थिति को कम करने के लिए।

अनुलग्नक 3: रक्षा व्यय के उपयोग और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल।

बजट प्रदर्शन

2020-21 के लिए सिविल एस्टिमेट और पेंशन सहित रक्षा बजट का आवंटन 4,71,378.00 करोड़ रुपये है, जो कि बीई 2019-20 से अधिक 40,367.71 करोड़ रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में निरपेक्ष मामले से पूंजीगत व्यय बढ़ा है। 2016-17 के बाद से आवंटित पूंजी बजट का पूरी तरह से उपयोग किया गया है, जो धन के आत्मसमर्पण के पिछले रुझानों को उलट रहा है। रक्षा बजट के उपयोग के चलन को वित्त वर्ष 2016-17 से भी उलट दिया गया है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) -2020:

- रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर, 2020 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) -2020 का अनावरण किया। डीएपी-2020 को सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारतीय घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने के साथ गठबंधन किया गया है, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के अंतिम उद्देश्य के साथ है। नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की घोषणा के साथ, डीएपी 2020 में भारतीय घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करते हुए आयात प्रतिस्थापन और निर्यात दोनों के लिए विनिर्माण हब स्थापित करने के लिए एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान शामिल हैं।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुछ प्रतिपादित विशिष्ट सुधार, निम्नानुसार हैं:
 - a) आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों/प्लेटफार्मों की एक सूची को सूचित करें। डीएपी में प्रासंगिक समावेशन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सूची में उल्लिखित कोई उपकरण पूर्व आयात पोस्ट की समयसीमा को अधिसूचित नहीं किया गया है।
 - b) आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण:
 - i. सूचना के लिए अनुरोध (आरएफआई) - आरएफआई चरण संभावित विदेशी विक्रेताओं की निर्माण और प्रगतिशील / स्वदेशी इको सिस्टम को पुर्जों / उप घटक स्तर पर उत्तरोत्तर विकसित करने की इच्छा का पता लगाएगा।
 - ii. खरीद की नई श्रेणी (भारत में वैश्विक निर्माण) - नई श्रेणी में भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से उपकरणों के पूरे / हिस्से या पुर्जों / असंबली / सब-असंबली / रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा का निर्माण शामिल है।
 - iii. आईजीए (इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट) के माध्यम से सह-उत्पादन - यह आईजीए आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से सह-उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और जीवन चक्र लागत को कम करने में सक्षम बनाता है।
 - iv. संविदात्मक सक्षमता। स्वदेशी इको सिस्टम के माध्यम से जीवन चक्र समर्थन लागत और सिस्टम संवर्द्धन को अनुकूलित करने के लिए क्रेता का अधिकार शामिल है।

- c) रक्षा विनिर्माण में एफडीआई: नई एफडीआई नीति की घोषणा के साथ, विदेशी ओईएम को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से 'विनिर्माण/रखरखाव संस्थाओं' की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किए गए नए वर्ग 'खरीद (वैश्विक - भारत में निर्माण)' जैसे उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है, घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक सुरक्षा को सक्षम करते हुए।
- d) समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेजी से निर्णय लेना: आत्मनिर्भर अभियान में घोषित रक्षा सुधार के एक भाग के रूप में, अनुबंध प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक पीएमयू की स्थापना अनिवार्य है। पीएमयू अधिग्रहण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्श सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: समीक्षा के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सरलीकरण, प्रतिनिधिमंडल पर जोर देने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करना और प्रक्रिया उद्योग को कुछ विशिष्ट प्रावधानों के साथ अनुकूल बनाना था, जैसे समय को कम करने के लिए 500 करोड़ रुपये तक के सभी मामलों में एकल चरण समझौते।
 - मेक अँड इनोवेशन:
 - a) मेक आई (70% तक की सरकारी राशि) - 250 करोड़ रुपये/ डीए की कैप और बोली मानदंडों के आधार पर डीए का चयन।
 - b) मेक II (उद्योग वित्त पोषित) स्वदेश निर्मित और विकसित हथियार / उपकरण / प्रणालियों / उप घटकों / विधानसभाओं के साथ साथ प्लेटफार्मों के उत्पादन के लिए।
 - c) मेक III (स्वदेशी रूप से निर्मित) श्रेणी के निर्माण के लिए उपकरण / प्लेटफार्मों या पुर्जों / असेंबली / उप-असेंबली को बढ़ाने के लिए सक्षम करने के लिए।
 - d) आइडेक्स, प्रौद्योगिकी विकास कोष और आंतरिक सेवा संगठनों जैसी विभिन्न पहलों के तहत इनोवेशन के माध्यम से विकसित प्रोटोटाइप की खरीद की सुविधा दी गई है।
 - ऑफसेट: ऑफसेट दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है, जिसमें घटकों पर पूर्ण रक्षा उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी और ऑफसेट के निर्वहन में प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न गुणक जोड़े गए हैं।

रक्षा उत्पादन में सेल्फ-रिलायंस:

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता/सेल्फ-रिलायंस हासिल करने और भारत को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र (ओएफएस), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक हब बनाने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है और उत्पाद रेंज को चौड़ा किया है। आर एंड डी पहल के माध्यम से और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रमुख उत्पादों को विकसित किया गया है। एक नीति के रूप में, डीपीएसयू और ओएफओं अपनी आवश्यकता के कई आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादन के मूल्य के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का मूल्य 41.70% है। इन वर्षों में एक विस्तृत विक्रेता आधार विकसित किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में मध्यम और लघु उद्योग और बड़े पैमाने पर उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा, डीपीएसयू और ओएफएस उपकरण और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 31.03.2020 को स्वदेशी सामग्री (स्वदेशीकरण की डिग्री) 74.56% थी।

नीति की पहल

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) ऑर्डर 2017 के नवीनतम पसंद के तहत, रक्षा उत्पादन विभाग ने 46 वस्तुओं की सूची को अधिसूचित किया है, जिसके लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतियोगिता है और इस प्रकार, इन वस्तुओं की खरीद केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी, चाहे खरीद मूल्य कुछ भी हो

रक्षा के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) को 2018 में लॉन्च किया, जिसमें एमएसएमई, स्टार्ट-अप, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, आरएंडडी इंस्टीट्यूट्स और एकेडमिया सहित उद्योगों को शामिल करने और उन्हें अनुदान / धन उपलब्ध कराने का इरादा है और आरएंडडी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सहायता, जिसमें भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस जरूरतों के लिए भविष्य में अपनाने की क्षमता है। डीडीपी के तहत जनवरी 2018 से डिफेंस इन्वेस्टर सेल कार्यात्मक अपने प्रश्न / शिकायतों के बारे में रक्षा उद्यमियों को सुविधा और मार्गदर्शक की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने देश भर से ऐसे 1000 से अधिक प्रश्नों / मामलों को संबोधित किया है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

मई 2001 में, रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक आरक्षित था, को 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए 100 प्रतिशत तक खोला गया था, दोनों लाइसेंसिंग के अधीन थे। एफडीआई नीति को आगे प्रेस नोट नंबर 4 (2020 सीरीज) दिनांक 17.09.2020 से उदारीकृत किया गया और स्वचालित मार्ग के तहत 74% और 74% से ऊपर सरकारी मार्ग के माध्यम से अनुमति दी गई है जहाँ भी आधुनिक प्रौद्योगिकी या इसके लिए उपयोग करने की संभावना है दर्ज किए जाने के अन्य कारण है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्र सुरक्षा के आधार पर जांच के अधीन होगा और सरकार के पास रक्षा क्षेत्र में किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित या प्रभावित कर सकता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रक्षा उद्योग क्षेत्र खोलने के बाद, अब तक सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में 44 एफडीआई प्रस्तावों / संयुक्त उपक्रमों को मंजूरी दी गई है। डीपीआईआईटी ने रक्षा वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए सितंबर 2020 तक निजी कंपनियों को 496 औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) जारी किए हैं।

निर्यात प्रोत्साहन

वित्त वर्ष में आयुध निर्माणी बोर्ड/ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी), डीपीएसयू और निजी क्षेत्र (डीडीपी द्वारा जारी प्राधिकरण के आधार पर) का निर्यात वित्त वर्ष 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 9116 करोड़ रुपये हो गया है।

रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 'मेक' प्रोसीजर को और अधिक सरलीकृत किया गया है और इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 w-e-f 01.10.2020 के अध्याय -3 के रूप में शामिल किया गया है। "मेक-I और मेक-II 'श्रेणियों के अलावा, एक नई श्रेणी' मेक-III 'को एक उद्देश्य के साथ पेश किया गया है ताकि देश में निर्मित सेवा की सूची में पहले से ही रक्षा वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भले ही भारत में डिजाइन और विकास नहीं किया गया हो। आयुध कारखानों/ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में 'मेक-II' प्रक्रिया को लागू करने की रूपरेखा भी फरवरी 2019 में जारी की गई थी, जिससे उन्हें भारतीय निजी उद्योग के माध्यम से विशेष रूप से आयात प्रतिस्थापन प्रकृति की वस्तुओं का स्वदेशीकरण करने में सक्षम बनाया गया था।

वित्त वर्ष में आयुध निर्माणी बोर्ड/ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी), डीपीएसयू और निजी क्षेत्र (डीडीपी द्वारा जारी प्राधिकरण के आधार पर) का निर्यात वित्त वर्ष 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 9116 करोड़ रुपये हो गया है।

रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास/डेवलपमेंट और निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 'मेक' प्रोसीजर को और अधिक सरलीकृत किया गया है और इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020

w-e-f 01.10.2020 के अध्याय-3 के रूप में शामिल किया गया है। “मेक-आई और मेक-II ‘श्रेणियों के अलावा, एक नई श्रेणी ‘मेक-III’ को एक उद्देश्य के साथ पेश किया गया है ताकि अगर भारत में डिजाइन और विकास नहीं किया गया हो भी देश में निर्मित सेवा की सूची में पहले से ही रक्षा वस्तुओं को प्राप्त किया जा सके। फरवरी 2019 में आयुध कारखानों और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में ‘मेक-II’ प्रक्रिया को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिससे वे विशेष रूप से भारतीय निजी उद्योग के माध्यम से वस्तुओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे सकें, विशेष रूप से आयात प्रतिस्थापन प्रकृति।